@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, बुधवार, 13 मई 2026, वर्ष-1, अंक-179, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'सिस्टम' का ट्रेलर रिलीज ...पेज-8

छात्रों की मेहनत और सपनों को कुचला, नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनियमितताओं के आरोपों के चलते मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को रद्द किए जाने के बाद आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तथाकथित अमृतकाल अब 'विषकाल' बन गया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने सीबीआई को इन 'अनियमितताओं' की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। एनटीए ने कहा कि यह परीक्षा अलग से अधिसूचित तिथियों पर पुनः आयोजित की जायेगी।

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला- पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार।

उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ़ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सज़ा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, अगर तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है। बाद में उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए कि नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का महानिदेशक कौन था, और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है।

उन्होंने दावा किया, साफ़ है कि मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में ख़ुद साझेदार हैं। जिस बाज़ार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति की 371वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केवल 2024 में ही एनटीए द्वारा आयोजित 14 राष्ट्रीय परीक्षाओं में से 5 में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले सामने आए। उन्होंने कहा, 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने स्वीकार किया था कि एनटीए को 'बहुत सुधार की जरूरत' है। दो साल बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस स्वीकारोक्ति के बाद आखिर क्या कार्रवाई हुई।

रमेश ने कहा कि अब यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल सुधार नहीं, बल्कि उससे जुड़े पूरे तंत्र के बुनियादी पुनर्गठन की जरूरत है, ताकि इसे मोदी सरकार के भ्रष्ट हाथों से बाहर रखा जा सके।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

सार समाचार

भारत-म्यांमार सीमा पर तनाव बढ़ा

कामजोंग,एजेंसी। मणिपुर के कामजोंग जिले और म्यांमार के बीच स्थित अस्थिर सीमा पर बसे कुकी समुदाय के गांव मोल्नोई में आग लगने की घटना के बाद विरोधाभासी खबरें और तीखे आरोप सामने आए हैं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जहां स्थानीय समुदाय के नेताओं ने तुरंत इन दावों का खंडन किया और आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्टीकरण जारी किया। मंगलवार दोपहर को सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगीं कि एनएससीएन (पूर्वी मोर्चा) से जुड़े उग्रवादियों ने सीमा पार कर मोल्नोई गांव में आग लगा दी।

कुकी समुदाय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर शुरुआती दावों में कहा गया कि यह हमला सीमा क्षेत्र में उनके समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। सरकारी अधिकारियों ने हिंसा के भारतीय धरती पर होने की अफवाहों को खारिज करते हुए तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों ने पुष्टि की कि मोल्नोई कुकी गांव पूरी तरह से म्यांमार के भीतर स्थित है, जो सीमा स्तंभ (बीपी) संख्या 113 से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आधिकारिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह घटना भारत से संबंधित नहीं है। यह घटना म्यांमार का आंतरिक मामला है।

आज से असम दौरे पर रहेंगे भागवत

गुवाहाटी,एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को तीन दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे। इस दौरान वह संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आरएसएस पदाधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरएसएस पदाधिकारियों के अनुसार, भागवत राज्य में आयोजित 'कार्यकर्ता विकास वर्ग (द्वितीय वर्ष)' प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संघ के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास गतिविधियों का हिस्सा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों से स्वयंसेवक भाग लेंगे। तीन दिवसीय कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ नेता और प्रचारक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, आरएसएस प्रमुख प्रतिभागियों को संगठन विस्तार, सामाजिक संपर्क, राष्ट्र निर्माण की पहल और देशभर में जमीनी स्तर पर गतिविधियों को मजबूत करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर संबोधित कर सकते हैं। अपने दौरे में भागवत असम और पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।

'कार्यकर्ता विकास वर्ग' आरएसएस का एक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम माना जाता है।

नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, आतंकवादी ढेर

जम्मू, एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार को भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान एक घुसपैठिया आतंकवादी मारा गया। नागरोटा स्थित सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, लगातार निगरानी के दौरान शाम करीब 4 बजे कृष्णा घाटी सेक्टर, पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय क्षेत्र के लगभग 300 मीटर अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। पोस्ट में कहा गया, व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की सेंध नहीं लगने दी।

एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। हमारे जवान इलाके में पूरी तरह तैनात हैं और पूरे सेक्टर में उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए हैं। पोस्ट में आगे कहा गया, नाइट कोर हमेशा

सतर्क है। हर घुसपैठ की कोशिश नाकाम होगी। हम सेवा करते हैं, हम सुरक्षा करते हैं! सेना के अनुसार, यह घटना कृष्णा घाटी के अग्रिम इलाके में नियंत्रण रेखा पर हुई, जब सतर्क जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को देखा और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू-कश्मीर में लगभग 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है, जो कश्मीर घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों तथा जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है।

असम के मुख्यमंत्री के रूप में हिमंत ने ली शपथ

गुवाहाटी, एजेंसी। हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। इसी के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता की बागडोर संभाल ली। हिमंत के साथ चार विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें भाजपा की अजंता नियोग और रामेश्वर तेली तथा राजग के सहयोगी दल असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा क्षेत्र में वेटरनरी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में हिमंत और चारों मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सरबानंद सोनोवाल और पबित्रा मार्गेरिटा, राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे।

पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी मामले की जांच

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने सीबीआई को इन 'अनियमितताओं' की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा अब नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथियां अलग से अधिसूचित की जाएंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी एक बयान में कहा कि यह निर्णय पारदर्शिता बनाए रखने और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को बरकरार रखने के लिए लिया गया है।

उसने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एनटीए द्वारा तथ्यों को परखे जाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने तीन मई 2026 को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को भारत सरकार की मंजूरी से रद्द करने और अलग से अधिसूचित तिथियों पर परीक्षा पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा तीन मई को भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा लगभग 23 लाख पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गयी थी।एजेंसी ने कहा कि प्राप्त सूचनाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि 'वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं है।'

उसने कहा,पुनः होने वाली परीक्षा की तिथियां और उनके लिए जारी किये जाने वाले प्रवेश पत्र की

समय-सारणी अगले कुछ दिनों में एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से सूचित की जाएगी। एनटीए ने कहा कि सरकार ने परीक्षा से जुड़े आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है। उसने कहा, एनटीए सीबीआई को पूरा सहयोग देगी और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता प्रदान करेगी।

एनटीए ने कहा, यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में भरोसे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

एजेंसी ने स्वीकार किया कि परीक्षा को दोबारा आयोजित करने से परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को 'वाकई बड़ी असुविधा' होगी। उसने कहा कि लेकिन परीक्षा प्रणाली में विश्वास को 'बड़ी और स्थायी क्षति' से बचाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। एनटीए के अनुसार, मई 2026 के सत्र में पंजीकृत उम्मीदवारों की जानकारी और चुने गए परीक्षा केंद्रों को पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बयान में कहा गया है, नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बयान के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर पुनः आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की नयी तारीखें और संशोधित प्रवेश पत्र की समय सारणी की सूचना आने वाले दिनों में आधिकारिक चैनलों के माध्यम से दी जायेगी तथा परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों को सलाह है कि वे केवल एजेंसी द्वारा जारी की गई सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें।

एनटीए ने रविवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि प्रश्न पत्रों को 'जीपीएस-ट्रैकिंग' वाले वाहनों में ले जाया गया था, जिन पर विशिष्ट, 'ट्रेस' करने योग्य 'वॉटरमार्क' लगे थे तथा परीक्षा केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से एआई-सहायता प्राप्त सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से की गई थी।

उसने कहा था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट (यूजी) 2026 से संबंधित कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की जानकारी है। तीन मई, 2026 को परीक्षा निर्धारित समय पर और पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। एजेंसी के अनुसार, कथित कदाचार से संबंधित सूचनाएं परीक्षा के चार दिन बाद सात मई की शाम को प्राप्त हुईं जिसे आठ मई की सुबह 'स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई' के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया गया।

नीट परीक्षा फिर से आयोजित करने की प्रक्रिया सात से 10 दिन में शुरू होगी: एनटीए महानिदेशक

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के चलते नीट-यूजी 2026 को रद्द करने की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि फिर से परीक्षा का कार्यक्रम अगले सात से दस दिन के भीतर घोषित किया जाएगा। एनटीए ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को इन अनियमितताओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। सिंह ने कहा, फिर से परीक्षा की तारीख के लिए, मैं अपनी टीम के साथ बैठक करूंगा और अगले कुछ दिनों में परीक्षा का पूरा कार्यक्रम और तारीखें घोषित करूंगा। हमारा प्रयास रहेगा कि परीक्षा जल्द आयोजित की जाए ताकि मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रवेश कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। यह प्रक्रिया अगले सात से दस दिन के भीतर शुरू हो जाएगी।

उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया सनातन धर्म विरोधी बयान

चेन्नई, एजेंसी।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उन्होंने इसे 'समाप्त' करने का आह्वान किया। उदयनिधि इससे पहले सितंबर 2023 में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में द्रमुक नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष, तमिल प्रार्थना गीत तमिल थाई वझुथु को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा, सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।

इससे पहले उदयनिधि ने 2023 में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी

जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। उन्हें हिंदू समर्थक संगठनों की आलोचना का शिकार होना पड़ा और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज कराए गए थे।

उदयनिधि ने नयी सरकार के हालिया शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में एक विशिष्ट शिकायत को उजागर करते हुए कहा कि राज्य के गीत को उसकी पारंपरिक प्राथमिकता के बजाय क्रम में तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया।

विपक्ष के नेता ने कहा, आपकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई ऐसी घटना एक गलती थी और आपको इस विधानसभा में इसे दोबारा होने नहीं देना चाहिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि न केवल विधानसभा में, बल्कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम या तमिलनाडु में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में, 'तमिल थाई वझथु' को हमेशा प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कभी समझौता न हो। हमें अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना होगा। उन्होंने दावा किया कि इस परंपरा से हटने से राज्य के लोगों में काफी आक्रोश है और उन्हें सदमा लगा है।

शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ टीवीके विधायक की याचिका पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुख्यमंत्री विजय के एक वोट की लड़ाई

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मतदान में हिस्सा लेने से रोकने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले टीवीके के एक विधायक की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा

प्रस्तुत किया गया। पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने पर सहमति जताई।

सेतुपति ने शिवगंगई जिले के नंबर 185 तिरुपत्तुर विधानसभा क्षेत्र में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता एवं पूर्व मंत्री के. आर. पेरियाकरुप्पन के खिलाफ एक मत के अंतर से जीत हासिल की थी।

इसके बाद पेरियाकरुप्पन ने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सेतुपति के, तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत समेत किसी भी मतदान में हिस्सा लेने पर अंतरिम रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रीनिवास सेतुपति किसी अविश्वास प्रस्ताव पर भी मतदान नहीं कर सकेंगे। इस आदेश का तमिलनाडु विधानसभा की 234 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

वर्तमान में इस गठबंधन को 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

सेतुपति को मतदान की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिए जाने के कारण, सदन में उसकी प्रभावी संख्या घटकर 119 हो जाएगी।

उच्च न्यायालय के समक्ष, पेरियाकरुप्पन ने आरोप लगाया कि तिरुपत्तुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 185 के लिए भेजा जाने वाला एक डाक मतपत्र गलती से तिरुपत्तुर जिले के तिरुपत्तुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 में भेज दिया गया था।

उन्होंने कहा कि मतपत्र को विचार के लिए सही निर्वाचन अधिकारी के पास भेजने के बजाय वहीं खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती में कथित विसंगतियों की ओर भी इशारा किया और दावा किया कि मतगणना रिकॉर्ड और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के बीच 18 मतों का अंतर था।

अंतरिम आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने पाया कि सीमित निर्देश के लिए प्रथमदृष्टया मजबूत मामला बनता है। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि यह आदेश सेतुपति के निर्वाचन को रद्द नहीं करता और न ही पेरियाकरुप्पन को निर्वाचित घोषित किये जाने का कोई अधिकार प्रदान करता है।

केरल के मुख्यमंत्री के नाम की आज हो सकती है घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस आलकमान ने केरल के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्षों समेत कई नेताओं के साथ मंगलवार को मंथन किया और बुधवार को नाम की घोषणा की जा सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बुधवार को की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास '10 जनपथ' पर हुई बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और कन्नूर से लोकसभा सदस्य के. सुधाकरन के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम.एम. हसन और के. मुरलीधरन तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों पी.सी. विष्णुनाथ, शफी परम्बिल और ए.पी. अनिल कुमार के साथ अलग-अलग मंथन किया।

मुरलीधरन का कहना है कि मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सोनिया गांधी से भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे वीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सुधाकरन ने संवाददाताओं से कहा कि इस मुद्दे पर उनका रुख नहीं बदला है और उनका यही मानना है कि मुख्यमंत्री का फैसला करते समय विधायकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी. राधाकृष्णन ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आलाकामन को अपनी राय से अवगत कराया है।

जो एजेंसियां संतोषजनक काम नहीं कर रहीं उन्हें ब्लैकलिस्ट करें: राव इंद्रजीत सिंह

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक।

गुरुग्राम,एजेंसी।

केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति मंऔ खड़े व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना है, इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सडक़, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों मंर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

वे मंगलवार को गुरुग्राम में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ले रहे थे। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी से बढ़ती आबादी वाले गुरुग्राम में जल संरक्षण और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बरसाती तथा उपचारित पानी का पुनः उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ भूजल रिचार्ज की दिशा में भी गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में एंबियंस मॉल के नजदीक बरसाती नालों तथा सडक़ पर कब्जे के संदर्भ में कमेटी के माध्यम से जांच करने के निर्देश भी दिए। बैठक में नरसिंहपुर में बनाई जा रही पक्की ड्रेन की प्रगति की जानकारी भी सांझा की गई। केंद्रीय मंत्री ने शहर में सडक़ सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों के कारण पूर्व में रखरखाव कार्य प्रभावित हुए हैं और व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं रही हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही नई एजेंसियों को चिन्हित कर कार्य में तेजी लाई जाए।

केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर बढ़ रहे सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन) वेस्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इसके स्थायी समाधान के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सी एंड डी वेस्ट के मामलों में अब तक करीब दो करोड़ रुपये के चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की रिकवरी भी हो चुकी है। राव ने बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी वेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आसपास के क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्रेनो वेस्ट में मेट्रो की मांग तेज

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो परियोजना को जल्द शुरू कराने की मांग अब और तेज हो गई है। गौतमबुद्ध नगर विकास समिति की ओर से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर क्षेत्र में मेट्रो सुविधा की आवश्यकता को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेजी से बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव के बीच मेट्रो परियोजना अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरी शहरी आवश्यकता बन चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और ईंधन बचत की अपील के बाद यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेट्रो परियोजना को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक जमीन पर कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। अब हस्ताक्षर अभियान पूरा होने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल सभी हस्ताक्षरों और दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर जनता की मांग औपचारिक रूप से रखेगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ग्रेनो वेस्ट में प्रतिदिन लंबा यातायात जाम, यात्रा में लगने वाला अधिक समय और बढ़ता ईंधन खर्च लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना समय की जरूरत है।

अनूप सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने वाली अपील के बाद लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेनो वेस्ट में मेट्रो अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है और इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। रश्मि पांडेर ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान जनता की वास्तविक आवाज है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा महंगा

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने की तैयारी के बीच अब यमुना एक्सप्रेसवे पर भी सफर महंगा होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी सुरक्षा रियलिटी ने यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) को टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, अभी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन कंपनी ने कंसेशन एग्रीमेंट का हवाला देकर टोल बढ़ाने की मांग की है। नई प्रस्तावित दरों में साढ़े तीन प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में पिछली बार अक्तूबर 2024 में 3.78 प्रतिशत का इजाफा किया गया था।

अब एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी सुरक्षा रियलटी ने होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर नई दरें लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी का कहना है कि रियायत समझौते के तहत हर वर्ष टोल दरों में संशोधन का प्रावधान है। प्रस्ताव के अनुसार कार, बस और ट्रकों समेत सभी श्रेणियों के वाहनों के टोल शुल्क में वृद्धि हो सकती है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ग्रेनो से आगरा तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों को अधिक टोल चुकाना पड़ेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंपनी ने यह संशोधित दरें लागू करने की तैयारी की है। हालांकि, यीडा के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर कंपनी और यीडा अधिकरियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। वहीं, टोल दरों में संभावित बढ़ोतरी से नियमित यात्रियों और व्यावसायिक वाहन चालकों की चिंता भी बढ़ गई है।

सपा प्रवक्ता के बयान पर बढ़ा विवाद, ब्राह्मण और गुर्जर समाज ने जताया विरोध

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की कथित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। ब्राह्मण और गुर्जर समाज के लोगों ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे आपत्तिजनक बताया है। वहीं राजकुमार भाटी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। विवाद पांच मई को दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित 'जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु' नामक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान दिए गए वक्तव्य से जुड़ा है। कार्यक्रम का एक वीडियो सामाजिक माध्यमों पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया।

ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि कार्यक्रम में एक कहावत के माध्यम से समाज विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। विरोध करने वालों का कहना है कि राजकुमार भाटी पहले भी ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में दिए गए पुराने बयान का भी उल्लेख किया। वहीं, राजकुमार भाटी ने सफाई देते हुए कहा कि वह सभी समाजों का सम्मान करते हैं और कार्यक्रम में विभिन्न जातियों से जुड़ी कहावतों का संदर्भ दिया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वीडियो के एक हिस्से को काटकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।

राजकुमार भाटी ने कहा कि कार्यक्रम का विषय जाति आधारित कहावतों और सामाजिक सोच पर केंद्रित था। उन्होंने दावा किया कि उसी क्रम में गुर्जर समाज से जुड़ी कहावत का भी जिक्र किया गया था, लेकिन केवल एक हिस्से को वायरल कर विवाद पैदा किया गया। इस बीच भाजपा ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है और समाज को बांटने का काम करती रही है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की भाषा और बयानबाजी से उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। विवाद के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

महिला ने नहर में कूदकर जान दी

पलवल,एजेंसी।

चांदहट थाना क्षेत्र अंतर्गत अलावलपुर चौकी के समीप सोमवार देर शाम करीब 25 वर्षीय महिला ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है।जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी खोजबीन और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से महिला के शव को नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के गांवों और थानों में महिला के हुलिए और कपड़ों के आधार पर जानकारी साझा कर रही है ताकि उसकी पहचान की जा सके।

रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हाईनिस सोसाइटी के दो टावरों में रहने वाले करीब 300 अधिक परिवार रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक न प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई शुरू की और न ही बिल्डर प्रबंधन इस दिशा में पहल कर रहा। सोसाइटी में रहने वाले संजीव शर्मा और अनुज ने बताया कि 9 अप्रैल को आए आदेश में हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को निर्देश दिए थे कि मामले की नियमानुसार जांच कर तीन महीने के भीतर फ्लैटों की रजिस्ट्री को लेकर निर्णय लिया जाए।

आदेश जारी होने के करीब डेढ़ महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब तक प्राधिकरण और बिल्डर की ओर से कोई अधिकारी सोसाइटी में आकर निवासियों से नहीं मिला है। साथ ही जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी है, उनकी सूची भी बिल्डर ने प्राधिकरण को नहीं सौंपी है।

युवक से मारपीट मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

नोएडा,एजेंसी।

सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने मामूली विवाद में युवक के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल बाइक और स्कूटी भी बरामद कर ली। मारपीट के दौरान पीड़ित युवक की सोने की चेन भी टूटकर गिर गई थी। उसे भी बरामद कर लिया गया है। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सात मई को एक युवक ने थाने में शिकायत दी कि जीआईपी चौकी के पास स्कूटी सवार ने गलत दिशा से आकर उसे टक्कर मार दी।

युवक ने जब इसका विरोध किया तो स्कूटी सवार युवक ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। सभी ने मिलकर युवक के साथ दोबारा गाली-गलौज और मारपीट की। इस दौरान युवक की सोने की चेन वहीं पर गिर गई। वारदात के समय पीडित युवक के साथ उसकी बहन भी थी, जो वर्तमान में यूपी पुलिस में है। उसकी सेक्टर-39 थाने में तैनाती है। मारपीट में शामिल आरोपियों की पहचान न्यू अशोकनगर निवासी अजीत सिंह, कपिल चौहान, राशिद और नया बांस गांव निवासी गौरव दत्त के रूप में हुई। आरोपियों के पास से दो चाकू भी बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल वे लोगों को डराने के लिए करते थे।

यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए तीन सीवर शोधन संयंत्र बनेंगे

गुरुग्राम,एजेंसी।

यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए तीन नए सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण होगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एक एसटीपी के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जबकि एक महीने के अंदर दो और एसटीपी के निर्माण के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। जीएमडीए ने गांव नौरंगपुर में 40 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन), गांव धनवापुर और सेक्टर-107 में 100-100 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण की योजना बनाई है। गांव नौरंगपुर के एसटीपी निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है।

इसके निर्माण में करीब 63 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें 90 एमएलडी क्षमता का पंपिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण में करीब दो साल का समय लगेगा। सेक्टर-80 स्थित मॉनसून ब्रिज सोसाइटी के समीप करीब पौने तीन एकड़ में इस एसटीपी के निर्माण के लिए जमीन का चयन किया है।गांव धनवापुर में मौजूदा समय में एसटीपी है, लेकिन इसकी क्षमता कम है। इस वजह से करीब 100 एमएलडी सीवर का गंदा पानी बिना शोधित हुए यमुना में जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं कि यमुना में गंदा पानी नहीं डाला जाए। यदि जल्द ही समाधान नहीं किया जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण के तहत नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर-107 में 100 एमएलडी क्षमता के सीवर संयंत्र के निर्माण होने के बाद सेक्टर-81 से लेकर सेक्टर-115 तक विकसित रिहायशी और वाणिज्यिक इलाकों से आ रहे गंदे पानी को शोधित करके यमुना में डाला जाएगा। गांव दौलताबाद में 400 केवीए क्षमता के बिजली घर के समीप इस एसटीपी का निर्माण किया जाएगा।

गुरुग्राम से यमुना में करीब 150 एमएलडी गंदा पानी बिना शोधित हुए जा रहा है।

घर से लाखों की नगदी और जेवरात चोरी

बल्लभगढ़,एजेंसी।

सेक्टर-3 क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोर घर से लाखों रुपये की नगदी और सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अमित जटवानी निवासी सेक्टर-3 बल्लभगढ़ ने पुलिस चौकी सेक्टर-3 में दी शिकायत में बताया कि वह चावला कॉलोनी क्षेत्र में स्टेशनरी का काम करते हैं। 2 मई 2026 को करीब 11:30 बजे उनकी पत्नी मधु उर्फ रिया खाना देने के लिए दुकान पर आई थीं। इसके बाद दोपहर करीब 1:15 बजे जब वह वापस घर पहुंचीं तो मुख्य गेट का दरवाजा खुला मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो सभी कमरों में सामान बिखरा हुआ था। डबल बेड खोलकर देखने पर उसमें रखा नकद व सोने का सामान गायब मिला। उस समय घर पर कोई नहीं था और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे।

पीड़ित के अनुसार चोर करीब 4 से 5 लाख रुपये नकद, सोने के 2 गले के सेट, 4 चूड़ियां, 3 चैन, 3 सिक्के, 3 अंगूठियां तथा 2 जेंट्स अंगूठियां चोरी कर ले गए। चोरी हुए आभूषणों के बिल उनके पास नहीं हैं। परिवार ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन सामान का कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। 11 मई 2026 को पुलिस चौकी सेक्टर-3 में हेड कांस्टेबल द्वारा शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है।

फरीदाबाद जिले के कराए जा रहे विकास कार्यों की विजिलेंस जांच होगी

फरीदाबाद,एजेंसी।

जिले में हुए विकास कार्यों की विजिलेंस जांच होगी। अनियमितता मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार का खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को सेक्टर-12 लघु सचिवालय में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आदेश दिए। मंत्री ने संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले अफसरों को फटकार लगाई। बैठक में अतिक्रमण हटाने, अवैध जल कनेक्शन काटने और खराब मैनहोल ढक्कन तुरंत बदलने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने साफ कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम, जिला परिषद और मार्केट कमेटियों द्वारा बनाई गई सड़कों की विजिलेंस जांच कराई जाएगी। यदि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए वह विजिलेंस विभाग को पत्र लिखेंगे। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी विकास कार्य पूरे करने और उनकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सबसे जरूरी है।

बैठक में आगरा नहर किनारे चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला रखा जाए। दीवार खड़ी कर संपर्क मार्ग बंद करना उचित नहीं होगा। साथ ही आगरा नहर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के अभियान में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि विकास कार्यों के साथ जनता की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

बैठक में शहर में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नगर निगम और एचएसवीपी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और शहर के मुख्य मार्गों से विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए। खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए वहां ग्रीन बेल्ट विकसित करने को कहा गया। उन्होंने बाजारों में अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण कार्य कराने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि साफ-सुथरे और व्यवस्थित बाजारों से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी।

पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान रैनीवेल परियोजना से लिए गए अवैध जल कनेक्शनों पर कड़ा रुख अपनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एफएमडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्विस स्टेशन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा लिए गए अवैध कनेक्शन तुरंत हटाए जाएं। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।

नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, सेवा का संकल्प है: पूनम सहराय

गुरुग्राम,एजेंसी।

सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर्स की ओर से मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस धूमधाम से मनाया गया। बसई स्थित एक रेस्तरां में आयोजित नर्सिंग दिवस कार्यक्रम में सामाजिक संस्था प्रयोग फाउंडेशन की ओर से नर्सिंग ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया। नर्सिंग ऑफिसर्स ने सदैव सेवा, समर्पण और मानवता से काम करने की बात कही। कार्यक्रम में केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पूनम सहराय रहीं। इस मौके पर उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम की शुरुआत नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने एक स्वर में उन्हें नमन किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मानवता के साथ मरीजों की सेवा करने का संकल्प लिया। समारोह में नर्सिंग ऑफिसर्स ने जमकर डांस भी किया। कई नर्सिंग ऑफिसर्स यहां तक कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी अपनी ड्यूटी करके इस कार्यक्रम में पहुंची थीं। सभी ने एक-दूसरे को बधाई दी और समाज सेवा के संकल्प को दोहराया।

सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पूनम सहराय ने कार्यक्रम में पहुंचीं सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को प्रयोग फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र व धार्मिक पुस्तकें देकर सम्मानित किया। पूनम सहराय ने कहा कि नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, सेवा का संकल्प है। इस सेवा को हम नर्सिंग ऑफिसर्स हमेशा पूरे मन से करती हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में आना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मीयता से काम करने की प्रेरणा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात मरीजों की सेवा की। समाज में नर्सों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवा नर्सिंग ऑफिसर्स से मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने और प्रोफेशनल स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहने का आह्वान किया। अपने काम का सदा महत्व समझें और काम में 100 प्रतिशत योगदान दें।

RNI.No DLHIN/25/A2841 स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508 मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धः रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल का औचक निरीक्षण कर नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के वर्क कल्चर को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रीमती गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल का औचक निरीक्षण कर नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा, नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। डॉक्टर यदि उपचार करते हैं तो नर्सें अपनी ममता और देखभाल से मरीज को नया जीवन देती हैं। कठिन परिस्थितियों में आपका धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा है।

उन्होंने अस्पताल में कार्यरत विभिन्न राज्यों (केरल, राजस्थान, पंजाब आदि) के नर्सिंग स्टाफ से विशेष तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने-कोने से आए इन जांबाज स्वास्थ्यकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने संवाद के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना की रिकॉर्ड वृद्धि की है। उनको मिलने वाली राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 13,150 कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य वातावरण को बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 1,388 नर्सिंग अधिकारियों तथा 41 पैरामेडिकल कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। अस्पताल निरीक्षण के दौरान रेखा गुप्ता ने विभिन्न राज्यों से आए नर्सिंग स्टाफ से भी बातचीत की।

उन्होंने अस्पताल में कार्यरत विभिन्न राज्यों (केरल, राजस्थान, पंजाब आदि) के नर्सिंग स्टाफ से विशेष तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने-कोने से आए इन जांबाज स्वास्थ्यकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने संवाद के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना की रिकॉर्ड वृद्धि की है।

इस फैसले से 180 नर्सिंग इंटर्न्स को बड़ी राहत मिली है। इसी क्रम में, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के वर्क कल्चर को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मरीजों की सेवा में दिन-रात समर्पित रहने वाले नर्सिंग स्टाफ का सम्मान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने सभी नर्सों को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सेवा भावना के लिए उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए स्वास्थ्यकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कठिन परिस्थितियों में भी नर्सिंग स्टाफ जिस धैर्य और समर्पण के साथ सेवा देता है, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की सेवा में दिन-रात जुटे रहने वाले नर्सिंग कर्मियों का सम्मान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्यकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के वर्क कल्चर को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मरीजों की सेवा में दिन-रात समर्पित रहने वाले नर्सिंग स्टाफ का सम्मान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी उसके भीतर बैठे सत्ता के सौदागर हैं!

नई दिल्ली लिए देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज जितनी मजबूत दिखाई देती है, उसकी सबसे बड़ी वजह केवल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, संसाधनों की ताकत या चुनावी मशीनरी नहीं है। उससे भी बड़ा कारण कांग्रेस की अंदरूनी सड़ांध भी है। भाजपा ने विपक्ष को जितना नहीं हराया, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष ने खुद को हराया है और कांग्रेस तो मानो इस आत्मघाती राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है।

कभी यह पार्टी विचार, संघर्ष, त्याग और संगठन की पहचान मानी जाती थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता नहीं, विचारधारा के लिए लड़ता था। लेकिन आज हालत यह है कि पार्टी के भीतर विचारधारा पीछे छूट चुकी है और कुर्सी सबसे बड़ी राजनीति बन गई है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं का मेला बन गई हो, जहां हर नेता अपने लिए जगह तलाश रहा है और पार्टी धीरे-धीरे भीड़ में गुम होती जा रही है।

सबसे शर्मनाक दृश्य तब सामने आता है जब चुनाव जीतने के तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवालों पर वोट देती है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता जनता के फैसले को अपने निजी प्रमोशन लेटर की तरह पढ़ते हैं। सरकार बनते ही मानो संदेश यह होता है कि अब जनता बाद में, पहले कुर्सी तय होगी।

कर्नाटक में सरकार बनी तो कई चेहरे खुद को स्वाभाविक मुख्यमंत्री मानने लगे। हिमाचल में सत्ता मिली तो भीतर की नाराज़गी बाहर तक आ गई। तेलंगाना में जीत के बाद भी गुटबाज़ी खत्म नहीं हुई। यह सब भाजपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने के लिए अलग से मुद्दे खोजने ही नहीं पड़ते। कांग्रेस के नेता खुद रोज़ नए मुद्दे थाली में सजाकर दे देते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कांग्रेस में अब मेहनत करने वाले कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं बची। जो व्यक्ति पांच साल सड़क पर संघर्ष करता है, पुलिस की लाठियां खाता है, जनता के बीच पार्टी का झंडा उठाकर चलता है, वही सबसे आखिर में खड़ा दिखाई देता है। जबकि टीवी स्टूडियो में बहस करने वाले, दिल्ली में लॉबिंग करने वाले और चुनाव के वक्त पैराशूट से उतरने वाले नेता सत्ता के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। यह असंतुलन केवल संगठन को कमजोर नहीं करता, बल्कि कार्यकर्ताओं का मन भी तोड़ देता है।

आज कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा उद्योग "गुटबाज़ी" बन चुका है। हर राज्य में कई कांग्रेसें चल रही हैं। एक कांग्रेस वह है जो जनता के बीच दिखाई देती है और दूसरी वह जो दिल्ली के कमरों में चलती है। किसी नेता का पूरा समय भाजपा से लड़ने में नहीं, अपने ही साथी को रोकने में निकल जाता है। कहीं टिकट काटने की साजिश, कहीं भीतरघात, कहीं जानबूझकर कमजोर प्रचार कि यह सब अब अपवाद नहीं, कांग्रेस की पहचान बनता जा रहा है।

विडंबना देखिए, भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अपने भीतर लोकतांत्रिक अनुशासन तक नहीं बचा पा रही। पार्टी के मंच पर एकता दिखाई जाती है, लेकिन भीतर तलवारें खिंची रहती हैं। जनता सब देखती है। जनता समझती है कि जिस पार्टी के नेता आपस में भरोसा नहीं करते, वह देश को स्थिर विकल्प कैसे दे पाएगी? राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पर उतर रहे हैं। यात्राएं कर रहे हैं। संविधान, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी राजनीति में कम से कम एक वैचारिक आग्रह दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरी कांग्रेस उसी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान रही है? या फिर पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहता है?

कांग्रेस का संकट नेतृत्व से ज्यादा नीयत का संकट बन चुका है। कई नेताओं को भाजपा से लड़ने से ज्यादा अपनी प्रासंगिकता बचाने की चिंता रहती है। यही कारण है कि हर चुनाव हारने के बाद भी वही चेहरे बने रहते हैं, वही रणनीति चलती रहती है और वही लोग आत्ममंथन की बैठक में सबसे ऊंची आवाज़ में भाषण देते दिखाई देते हैं। हार की जिम्मेदारी कभी तय नहीं होती, लेकिन वफादारी के प्रमाणपत्र लगातार बांटे जाते रहते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि कांग्रेस धीरे-धीरे विपक्ष की उम्मीद कम और राजनीतिक निराशा ज्यादा बनती जा रही है। देश का एक बड़ा वर्ग भाजपा के विकल्प की तलाश में है। बेरोजगारी, महंगाई, संस्थाओं की निष्पक्षता, सामाजिक तनाव, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर एक मजबूत विपक्ष जनता का भरोसा जीत सकता है। लेकिन कांग्रेस हर बार अंतिम क्षणों में खुद अपने ही जाल में फंस जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं को भाजपा की ताकत से उतना डर नहीं लगता, जितना किसी मजबूत कांग्रेसी नेता के उभरने से लगता है। क्योंकि भाजपा से लड़ाई में मेहनत लगती है, जबकि भीतर की राजनीति में केवल चालाकी काफी होती है। यही वजह है कि संगठन निर्माण सबसे कमजोर क्षेत्र बन गया है। राज्यों में ऐसे नेताओं की भरमार है जिनकी राजनीति केवल दिल्ली दरबार तक सीमित है। जनता के बीच उनका कोई आधार नहीं, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ मजबूत रहती है।

यमुना के बाढ़ क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोकः दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने सुर घाट क्षेत्र में पार्किंग संचालन की अनुमति बहाल करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि सुर घाट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धार्मिक या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति न दी जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त भूमि पर पार्किंग या अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकतीं, चाहे वह किसी धार्मिक अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही क्यों न हों। मामला वर्ष 2022 में दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी उस निविदा से जुड़ा था, जो सुर घाट स्थित पार्किंग स्थल के रखरखाव के लिए निकाली गई थी।

यह निविदा दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत जारी की गई थी। याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह कार्य हासिल किया था और पार्किंग स्थल का संचालन भी शुरू कर दिया गया था। हालांकि बाद में वर्ष 2025 में डीडीए और एमसीडी ने यह आवंटन रद कर दिया। डीडीए ने अदालत को बताया कि संबंधित भूमि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में आती है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने डीडीए के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को जारी रखना उचित नहीं होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने निविदा रद करने के आदेश को सीधे चुनौती नहीं दी थी। यदि मुआवजे की मांग करनी है, तो इसके लिए अलग दीवानी वाद दायर किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि श्रद्धालुओं को पार्किंग सुविधा की आवश्यकता हो, तो डीडीए को यमुना के बाढ़ क्षेत्र से बाहर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि धार्मिक आयोजनों और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के दौरान लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए, लेकिन इससे यमुना के पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

अलमारी की चाबी बनाने के बहाने युवक ले गया 40 लाख के जेवरात

नई दिल्ली,साहस समाचार।

पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में कपड़ा कारोबारी युवक ने अपने घर की अलमारी की चाबी बनवाने के लिए गली में घूम रहे युवक को बुलाया। चाबी बनाने के दौरान आरोपी ने पीड़ित हरीश खन्ना (25) को बालों में उलझाकर कुछ-कुछ सामान मंगवाना शुरू किया। इस बीच आरोपी ने चुपचाप अलमारी से करीब 40 लाख के जेवरात चुरा लिए। बाद में आरोपी चाबी लगाने वाले स्थान पर तेल में भीगा रूई का फोया डालकर चला गया। जाते-जाते आरोपी ने कहा कि अभी 10 मिनट बाद चाबी लगाकर ताला खोल लेना। पीड़ित ने आरोपी को चाबी बनाने की पेमेंट भी कर दी। 10 मिनट बाद जब अलमारी खोली गई तो उसके होश उड़ गए। अलमारी में रखी करीब 250 ग्राम सोने व हीरे के जेवरात गायब थे।

बाद में शकरपुर थाना पुलिस को खबर दी गई। लोकल पुलिस के अलावा क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए। छानबीन के बाद शकरपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बदमाश के आने-जाने वाले रूट की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित हरीश खन्ना परिवार के साथ गली नंबर-1, मास्टर ब्लॉक, शकरपुर में रहते हैं। चांदनी चौक इलाके में इनकी कपड़े की दुकान है। रविवार शाम के समय यह घर पर मौजूद थे। इनकी एक अलमारी की चाबी पिछले काफी दिनों से खोई हुई थी। इस दौरान गली में एक युवक ताले-चाबी बनवाने की आवाज लगाने लगा।

हरीश ने आवाज देकर युवक को बुलाया। बाद में अंदर ले जाकर युवक को अलमारी को दिखाया गया। चाबी वाले युवक ने बताया कि चाबी बनाने के लिए वह 110 रुपये लेगा। बात होने पर युवक ने अपना काम शुरू कर दिया। आरोपी पीड़ित से इधर-उधर की बात करने लगा। इस बीच उसने रूई और सरसों का तेल मंगवाया। हरीश कुछ ही देर में घर से तेल व रूई ले आया। कुछ देर काम करने के बाद आरोपी ने चाबी वाले स्थान पर तेल में भीगी रूई उसमें डाली और 10 मिनट में खोलने की बात कर वहां से चला गया।

आरोपी के जाने के बाद पीड़ित ने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। वहां से काफी सारे जेवरात गायब थे। पुलिस को दी सूची में पीड़ित ने बताया कि दो हीरे की अंगूठी, 5 सोने की अंगूठी, दो चेन, हीरे के टॉप्स, सोने का लॉकेट, दो भारी कड़े, चार भारी चूड़ियां, गले का भारी हार व अन्य कई जेवरात गायब हैं।

जाकिर हुसैन कॉलेज सांध्य में मनाया गया वार्षिक उत्सव

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विरासत वाले कॉलेज जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज(सांध्य) में मंगलवार को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे तथा कारपोरेट अफेयर मामलों के राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए अपने छात्र जीवन को याद किया और कहा कि छात्र जीवन से उनका इस कॉलेज से जुड़ाव रहा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के तहत हो रहे बदलावों की बात की जिसके द्वारा पढ़ने वालों को शिक्षा के साथ समाज जीवन में जाने के लिए भी तैयार किया जाता है। उन्होंने यह ध्यान दिलाया कि पिछले बारह सालों के दौरान प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में रूपांतरकारी कामों को बढ़ावा दिया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 का निरसन हो, या विधायिका में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो।

उन्होंने युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि उनको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। इससे देश में चुनाव में फिजूलखर्च पर तो रोक लगेगी ही विकास का काम भी अनवरत चलता रहेगा। इस अवसर पर हर्ष मल्होत्रा ने कॉलेज का नया लोगो भी जारी किया। कार्यक्रम के आरंभ में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर भरत सिंह ने कॉलेज की विरासत का परिचय करवाया और कॉलेज की उपलब्धियों की चर्चा की। इस कार्यक्रम के संयोजक व जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर आसमी रज़ा ने भी छात्रों से संवाद किया और उनकी उपलब्धियों के लिये पुरस्कार दिये।

फर्जी निवेश गिरोह का मास्टरमाइंड निकला सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नई दिल्ली,साहस समाचार।

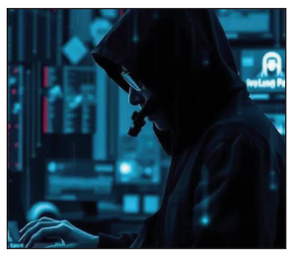

फर्जी निवेश एप और वेबसाइट के जरिए देशभर में लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकला है। साइबर थाना पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, बेंगलुरु और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना रवि राठौड़ तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर लोगों को नकली निवेश योजनाओं के जाल में फंसाता था। बताया जा रहा है कि वह एक बड़ी कंपनी में सालाना लगभग 30 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी कर चुका है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

जांच में पता चला है कि आरोपित सामाजिक माध्यमों और इंटरनेट मंचों पर ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा निवेश से जुड़े आकर्षक विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी मोबाइल एप और वेबसाइट से जोड़ा जाता था। शुरुआत में छोटी रकम पर नकली लाभ दिखाकर लोगों का भरोसा जीता जाता था।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जब निवेशक बड़ी रकम जमा कर देते थे तो आरोपित उनका खाता बंद कर देते थे या उन्हें एप और वेबसाइट से बाहर कर संपर्क तोड़ देते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह खासतौर पर युवाओं और ऑनलाइन ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले लोगों को निशाना बनाता था।

पुलिस का कहना है कि कई लोगों ने कम रकम गंवाने के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिससे ठगी की वास्तविक रकम और अधिक होने की आशंका है। अब पुलिस बैंक खातों के लेनदेन और दर्ज शिकायतों के आधार पर कुल ठगी का आंकड़ा जुटाने में लगी है। जांच में यह भी सामने आया है कि रवि राठौड़ ठगी की रकम से महंगी गाड़ियों और लग्जरी संपत्तियों का शौकीन बन गया था।

उसके इंदौर में कई आलीशान फ्लैट और संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ठगी की रकम को किन-किन माध्यमों से निवेश किया गया। वहीं, गिरोह से जुड़े सुदामा नामक आरोपित पर भी ठगी की रकम को स्थानीय क्रिकेट आयोजनों में लगाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वह खंडवा में आयोजित स्थानीय क्रिकेट लीग से जुड़ा हुआ था और एक टीम पर बड़ी रकम खर्च कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों को सक्रिय किया गया है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से फर्जी एप, वेबसाइट और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

विद्यार्थियों के समग्र विकास को शैक्षणिक वातावरण तैयार करना सरकार का उद्देश्यः सूद

नई दिल्ली,साहस समाचार।

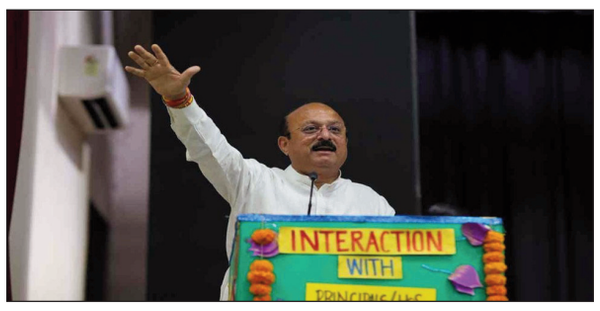

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल बेहतर परिणाम देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक, सुरक्षित और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। सूद ने आज शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में सभी प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ स्कूल्स से संवाद एवं समन्वय के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर आने वाली चुनौतियों को सीधे समझना, शिक्षकों एवं स्कूल प्रशासन के सुझाव प्राप्त करना तथा सरकारी विद्यालयों को आधुनिक, सशक्त और विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है।

उन्होंने अधिकारियों एवं विद्यालय प्रमुखों से कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल बेहतर परिणाम देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक, सुरक्षित और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। उन्होंने स्कूलों में अनुशासन, नियमित उपस्थिति, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों तथा विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों, विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास से ही विद्यार्थियों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

उन्होंने विद्यालय प्रमुखों से छात्रों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा नवाचार आधारित शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपील भी की। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हेड ऑफ़ स्कूल, शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रशासनिक अधिकारी, पेरेंट्स और अन्य सभी सहयोगी महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से नुकसान होता है, तो शिक्षा व्यवस्था में कमी पूरे समाज को प्रभावित करती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी और शिक्षक शिक्षा सुधार के कॉमन एजेंडा को पूरी निष्ठा और प्रमाणिकता से लागू करें। उन्होंने कहा कि एक हेड ऑफ़ इंस्टिट्यूशन की प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ-साथ एक जिम्मेदार नागरिक और सरकारी कर्मचारी के रूप में ईमानदारी से कार्य करना भी आवश्यक है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

वर्ष 2024-25 में जहां परीक्षा परिणाम 94.57 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 98.53 प्रतिशत हो गया, जो 3.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों ने हमेशा देश को योग्य नागरिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी और अन्य सफल पेशेवर दिए हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधन का महत्वपूर्ण विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय मानसिक तनाव का दौर है।

स्कूलों को केवल शैक्षणिक परिणामों पर नहीं बल्कि विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, तनाव, विषाद और भावनात्मक समस्याओं की पहचान पर भी ध्यान देना होगा । उन्होंने स्कूल सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि किसी भी स्कूल में कोई 'डार्क स्पॉट' नहीं होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार की अप्रिय या पाशविक घटना की संभावना हो।

नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर एनएसयूआई का प्रदर्शन

नई दिल्ली,साहस समाचार।

मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विवाद गहरा गया है। पेपर लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर एनएसयूआई ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय के पास प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं छात्र संगठन एबीवीपी ने मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

एनएसयूआई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व छात्र शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने में पूरी तरह विफल रही है। संगठन का कहना है कि परीक्षा रद्द होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही हुई है।

विनोद जाखड़ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय देशभर के लाखों छात्रों की आवाज़ की जीत है। यदि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होती तो सरकार को परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच के आदेश देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। एनएसयूआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एनटीए को भंग करने की भी मांग उठाई। इसके अलावा संगठन ने सवाल किया कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के साथ हुए अन्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा और कथित पेपर लीक नेटवर्क में शामिल गिरोहों पर कब कार्रवाई होगी।

वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षाओं की गोपनीयता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए तथा दोषियों, परीक्षा माफियाओं और सहयोगियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद नीट जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता उनके भविष्य और मनोबल पर प्रभाव डालती है।

संपादकीय

युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था की परीक्षा

भारत ने हमेशा कठिन समय में संयम, त्याग और राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया है। चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन का दौर रहा हो, 1965 और 1971 के युद्धों का समय हो या फिर महामारी जैसी वैश्विक आपदा-देश ने हर संकट में सामूहिक जिम्मेदारी निभाई। आज एक बार फिर देश ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहाँ सीमाओं पर तनाव, वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती आर्थिक चुनौतियाँ आम नागरिक की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से "एक साल तक सोना न खरीदने" की अपील केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सोच को दिशा देने वाला संदेश भी है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। भारतीय परिवारों में सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। विवाह से लेकर त्योहारों तक, सोने की खरीद भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। लेकिन यही आदत कई बार देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव भी डालती है। भारत हर वर्ष अरबों डॉलर का सोना आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है और व्यापार घाटा बढ़ता है। ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार युद्ध, तेल कीमतों और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे हों, तब अनावश्यक आयात पर नियंत्रण एक रणनीतिक आवश्यकता बन जाता है।

प्रधानमंत्री की अपील का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ता है। सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास करती है, लेकिन लंबे समय तक कृत्रिम राहत देना आसान नहीं होता। यही कारण है कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संतुलन बनाए रखने की है।

हालांकि यह भी सच है कि केवल जनता से त्याग की अपील करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि महंगाई आम आदमी की सहनशक्ति से बाहर न जाए। मध्यम वर्ग और गरीब तबका पहले से ही बढ़ती कीमतों, EMI, शिक्षा और इलाज के खर्चों से जूझ रहा है। ऐसे में यदि ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो सामाजिक असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए राष्ट्रहित और जनहित के बीच संतुलन बनाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। डिजिटल भुगतान, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा क्षेत्र में तेजी से विकास ने देश को मजबूत बनाया है। लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की असली परीक्षा संकट के समय होती है। युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते, उनका असर बाजारों, उद्योगों, नौकरियों और परिवारों तक पहुंचता है। यही वजह है कि आज आर्थिक राष्ट्रवाद की चर्चा फिर तेज हो रही है। देश को यह समझना होगा कि हर चमकती चीज निवेश नहीं होती और हर उपभोग आवश्यक नहीं होता। सोने की खरीद कम करने की अपील को यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए, तो यह आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार उपभोग की ओर बढ़ने का संकेत भी है। यदि देश का पैसा उत्पादन, उद्योग, स्टार्टअप और घरेलू निवेश में लगेगा, तो अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी। भारत को उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था से उत्पादन आधारित शक्ति बनने की आवश्यकता है। यह बदलाव केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सोच बदलने से संभव होगा। फिर भी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता त्याग तभी करती है, जब उसे व्यवस्था पर भरोसा हो। यदि लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, फिजूलखर्ची कम हो रही है और नीतियों में पारदर्शिता है, तब वे कठिन फैसलों को भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि आम आदमी पर बोझ बढ़े और सत्ता में बैठे लोग विलासिता में दिखाई दें, तो संदेश कमजोर पड़ जाता है। इसलिए नेतृत्व का नैतिक उदाहरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।

पीएम मोदी की अपील पर राहुल-अखिलेश की नकारात्मक राजनीति !

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

राहुल गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मोदी सरकार की आलोचना में शामिल दिखाई दे रहे हैं। यह वही राजनीति है जिसमें राष्ट्रीय संकट भी राजनीतिक अवसर बन जाता है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा विरोध की राजनीति में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें हर सरकारी पहल में खामी ही दिखाई देती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें यह समझ नहीं कि तेल की कीमतों का असर किसानों, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं पर कितना व्यापक पड़ता है? यदि सरकार पहले से लोगों को जागरूक कर रही है और विकल्प सुझा रही है तो इसमें गलत क्या है?

आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, वह सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक सप्लाई चेन पहले ही प्रभावित थी। अब पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने कच्चे तेल की आपूर्ति पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा कर रखी है। भारत जैसा देश, जोकि विश्व की विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, स्वभाविक है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, स्वाभाविक रूप से इस संकट से प्रभावित है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, अनावश्यक सोना खरीदने से बचने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है तो इसमें अनुचित क्या है?

यह अपील न तो किसी भय का संकेत थी और न ही किसी आपातकाल की घोषणा, बल्कि आर्थिक अनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश है, किंतु कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सरकार की विफलता बताकर राजनीतिक हमला शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या हर राष्ट्रीय चुनौती को राजनीति के चश्मे से देखना उचित है? क्या राष्ट्रहित में की गई अपील का मजाक उड़ाना जिम्मेदार विपक्ष की पहचान है?

आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, वह सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक सप्लाई चेन पहले ही प्रभावित थी। अब पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने कच्चे तेल की आपूर्ति पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। इस मार्ग में आई बाधा ने तेल की कीमतों में विस्फोटक वृद्धि कर दी है। जिसमें कि भारत लगभग 40 प्रतिशत कच्चा तेल और करीब 90 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है। अब ऐसी स्थिति में यदि सरकार जनता से ऊर्जा संरक्षण की अपील करती है तो यह उसकी दूरदर्शिता ही है, न कि विफलता।

वस्तुतः दुनिया के अधिकांश देश अपने नागरिकों से ऐसे समय में संयम और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जापान, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट के दौरान नागरिकों ने स्वेच्छा से बिजली और ईंधन की बचत की थी। वहां इसे राष्ट्रहित माना गया, लेकिन भारत में विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बनाने में जुट गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करें, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता दें तथा सोने की अनावश्यक खरीद से बचें। इनमें ऐसा क्या है जिसे राष्ट्रविरोधी या जनविरोधी कहा जाए? असल में यह अपील तीन स्तरों पर महत्वपूर्ण है, एक- विदेशी मुद्रा की बचत के संदर्भ में। भारत का व्यापार घाटा मुख्य रूप से तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात से बढ़ता है। सिर्फ सोने के आयात पर ही हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। दो- ऊर्जा सुरक्षा के लिए। तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। परिवहन महंगा होता है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और अंततः आम जनता प्रभावित होती है।

तीसरा इसका मुख्यकारण देश की आत्मनिर्भरता की दिशा तय करना है। क्योंकि 'वोकल फॉर लोकल', इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल कार्य संस्कृति- ये सभी दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री की अपील वर्तमान संकट से निकलने के लिए ही नहीं दिखती, यह तो भारत के हित में भविष्य की तैयारी भी है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की अपील को "सरकार की नाकामी" बताते हुए कहा कि जनता को त्याग और बचत की सलाह देना विफल शासन का प्रमाण है, किंतु कहना होगा कि यह तर्क बेहद सतही है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता, नागरिकों की भागीदारी उसमें बराबर की चाहिए रहती है। वस्तुतः राहुल गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे हर राष्ट्रीय मुद्दे में विरोध का अवसर खोजते हैं। चाहे सेना का मनोबल हो, विदेश नीति हो, वैक्सीन अभियान हो या आर्थिक अनुशासन, आप देखेंगे कि वे हर जगह नकारात्मकता उनकी राजनीति का आधार बनती हुई दिखी है।

विडंबना यह है कि जिन देशों की आर्थिक नीतियों की कांग्रेस अक्सर प्रशंसा करती है, वहां नागरिक अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अमेरिका और यूरोप में ऊर्जा संकट के दौरान सरकारों ने हीटिंग कम करने, सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने और ईंधन बचाने की अपील की थी। तब उसे जिम्मेदार नेतृत्व कहा गया था।

राहुल गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मोदी सरकार की आलोचना में शामिल दिखाई दे रहे हैं। यह वही राजनीति है जिसमें राष्ट्रीय संकट भी राजनीतिक अवसर बन जाता है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा विरोध की राजनीति में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें हर सरकारी पहल में खामी ही दिखाई देती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें यह समझ नहीं कि तेल की कीमतों का असर किसानों, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं पर कितना व्यापक पड़ता है? यदि सरकार पहले से लोगों को जागरूक कर रही है और विकल्प सुझा रही है तो इसमें गलत क्या है?

विपक्ष का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं होता, बल्कि संकट के समय सकारात्मक सहयोग देना भी होता है। दुर्भाग्य से आज का विपक्ष राष्ट्रहित से अधिक राजनीतिक लाभ-हानि पर केंद्रित दिखाई देता है। दूसरी ओर विपक्ष जिस प्रकार यह चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि देश में ईंधन संकट खड़ा हो गया है, वह वास्तविकता से दूर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कच्चे तेल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। किसी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी से कमी की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तेल विपणन कंपनियां वैश्विक कीमतें बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रखने का प्रयास कर रही हैं। कंपनियां प्रतिदिन भारी आर्थिक दबाव झेल रही हैं ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। यानी सरकार अपील ही नहीं कर रही, वह संकट से निपटने के लिए ठोस कदम भी उठा रही

कहना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मूलतः "साझी जिम्मेदारी" का संदेश है। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील आर्थिक अनुशासन, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जिम्मेदार पहल है। इसमें न तो भय फैलाने की कोशिश है और न ही जनता पर बोझ डालने का प्रयास। यह एक ऐसी चेतावनी है जो भविष्य की चुनौतियों के प्रति देश को तैयार करने का प्रयास करती है।इसके विपरीत राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रवैया राजनीतिक अवसरवाद अधिक प्रतीत होता है। उन्होंने न तो कोई वैकल्पिक समाधान दिया और न ही संकट की गंभीरता को स्वीकार किया।

अच्छा हो कि राजनीतिक दल कम से कम राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों पर परिपक्वता दिखाएं। यदि देश की ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता मजबूत रहती है तो उसका लाभ हर नागरिक को मिलेगा, चाहे वह किसी भी विचारधारा का समर्थक क्यों न हो।प्रधानमंत्री मोदी की अपील को राजनीति के बजाय राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

एनसीआरबी के आंकड़े और हमारे बच्चों से जुड़ी ये सच्चाई!

डॉ. निवेदिता शर्मा

देश में बढ़ती छात्र आत्महत्याएं हमारे सामने वर्तमान दौर की उस सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था का आईना है, जिसमें बचपन धीरे-धीरे दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के नीचे दम तोड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार वर्ष 2024 में 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की हैं। यह संख्या वर्ष 2023 की तुलना में 4.3 प्रतिशत अधिक है। इसमें सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि एक ओर देश में कुल आत्महत्या के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं छात्रों की आत्महत्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में यह स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि हमारे बच्चे शिक्षा के अतिरिक्त बोझ के नीचे मानसिक रूप से टूट रहे हैं।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आत्महत्या करने वाले छात्रों में बड़ी संख्या कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों की है। यह वह आयु है, जब बच्चों को सबसे अधिक भावनात्मक सहारे, संवाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, किंतु दुर्भाग्य से इस दौर में उन पर करियर चुनने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और "सफल" बनने का भारी दबाव डाल दिया जाता है।

वर्ष 2015 में छात्र आत्महत्या के 8,934 मामले थे, जो 2024 में बढ़कर 14,488 हो गए। यानी एक दशक में 62 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का होना निश्चित ही हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए! क्योंकि सामने आए साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन औसतन लगभग 35 छात्र अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। यहां विचार करनेवाली बात यह भी है कि क्या यह अकेले बच्चों की असफलता है? या समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था की सामूहिक विफलता है?

आज शिक्षा का अर्थ ज्ञान, संस्कार और व्यक्तित्व विकास न होकर ऐसा लगता है, जैसे कि प्रतियोगिता, रैंक, पैकेज और प्रतिष्ठा का पर्याय बन चुका है। बच्चों के कंधों पर इतना भारी बोझ डाल दिया गया है कि वे अपनी उम्र के सहज आनंद, खेल, जिज्ञासा और रचनात्मकता से दूर होते जा रहे हैं। विद्यालयों के बाद कोचिंग संस्थानों का दबाव, परीक्षा का भय, करियर की अनिश्चितता और अभिभावकों की अपेक्षाएं मिलकर बच्चों को मानसिक रूप से थका रही हैं।

बच्चों के सामने भावनात्मक अकेलेपन का संकट भी उभरकर सामने आया है। यही कारण है कि अनेक छात्र अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और भावनात्मक तनाव से जूझ रहे हैं, किंतु दुखद है कि समय रहते उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान तक नहीं हो पाती है! यदि बच्चा उदास है, चिड़चिड़ा है या अकेला रहने लगा है, तो इसे "जिद" या "कमजोरी" मान लिया जाता है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाता।

दूसरी ओर सच यह भी है कि बच्चा सबसे अधिक भय "असफल" कहलाने से महसूस करता है। उसे यह समझाया ही नहीं जाता कि जीवन में सफलता के अनेक रास्ते होते हैं। विद्यालयों और घरों में बच्चों को बार-बार तुलना का सामना करना पड़ता है। धीरे-धीरे बच्चा स्वयं को अंक और उपलब्धियों से मापने लगता है। जब अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच दूरी बढ़ती है, तब वह भीतर से टूटने लगता है।

ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि अभिभावक सबसे पहले यह समझें कि हर बच्चा अलग होता है। सभी बच्चों की क्षमता, रुचि और गति समान नहीं हो सकती। सफलता का अर्थ मेडिकल, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक सेवा नहीं है। यदि बच्चा संगीत, खेल, कला, लेखन, डिजाइन, कृषि या किसी अन्य क्षेत्र में रुचि रखता है, तो उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक बच्चों के साथ समय बिताएं। सिर्फ स्कूल की फीस भर देना या अच्छे कोचिंग संस्थान में भेज देने से उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। बच्चों को सबसे अधिक जरूरत अपने माता-पिता के विश्वास, संवाद और भावनात्मक सहारे की होती है। यदि बच्चा डर, तनाव या असफलता की बात कह रहा है, तो उसे डांटने के बजाय सुने। विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना कि विद्यालय पढ़ाई का केंद्र है, किंतु यह भी सच है कि बच्चों के भावनात्मक विकास का भी वह एक स्थान है, इसलिए यह जरूरी है कि हर विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर होने चाहिए। शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जाए कि वे बच्चों में तनाव और अवसाद के शुरुआती संकेत पहचान सकें। अनुशासन और परिणाम पर ध्यान देने के बजाय बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें।

इसके साथ ही समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। आज समाज को यह स्वीकार करना होगा कि बच्चों की जिंदगी किसी परीक्षा या प्रतिशत से कहीं अधिक मूल्यवान है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बच्चों को यह एहसास दिलाया जाए कि उनका जीवन किसी भी परीक्षा से बड़ा है। असफलता अंत नहीं होती। हार जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। कुल मिलाकर शिक्षा के अतिरिक्त बोझ से बच्चों को बाहर निकालने का अतिरिक्त श्रम स्कूल, अभिभावक, शिक्षक, समाज और व्यवस्था सभी को मिलकर आज करने की आवश्यकता है। तभी बच्चे किसी भी प्रकार के डर से बाहर निकल पाएंगे और एक नए आत्म-विश्वास में जी सकेंगे।

यदि हम अब भी नहीं चेते, तो आने वाले वर्षों में आंकड़े और भयावह हो सकते हैं। उम्मीद है, हम सभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सामने आए इन आंकड़ों पर गंभीर विचार अवश्य करेंगे और समाधान की दिशा में आगे आएंगे। कोई भी बच्चा आत्म-हत्या जैसा कदम न उठाए, हमारे सामूहिक प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए ।***(लेखिका मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं।)***

75 वर्षों में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना सोमनाथ

भारत की सांस्कृतिक आत्मा और आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होना केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की ऐतिहासिक चेतना, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी महत्वपूर्ण क्षण है। आज जब देश इस गौरवपूर्ण यात्रा को स्मरण कर रहा है, तब यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि केंद्र की भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की अदम्य शक्ति और सनातन परंपरा की अमर गाथा है।

सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत के संघर्ष, आक्रमणों और पुनर्जागरण की कहानी कहता है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई बार ध्वस्त किए जाने के बाद भी यह मंदिर भारतीय आस्था का केंद्र बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौहपुरुष सरदार पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। वर्ष 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसने स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान को नई पहचान दी।

इन 75 वर्षों में सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक बन गया। विशेष रूप से पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को जिस प्रकार गति दी है, वह उल्लेखनीय है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, अयोध्या में राम मंदिर और केदारनाथ पुनर्विकास जैसे अनेक प्रकल्प इस सोच को मजबूत करते हैं कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर ही विश्व में नई पहचान बना सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर यहां अपने श्राप से मुक्ति पाई थी, इसी कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन काल से श्रद्धा और व्यापार दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और यात्रावृांतों में मिलता है। सोमनाथ का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसकी अपार संपदा लूटी और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भी विभिन्न कालखंडों में कई विदेशी आक्रांताओं ने इसे निशाना बनाया। लेकिन हर विनाश के बाद भारतीय समाज ने इसे फिर से खड़ा किया। यही तथ्य दर्शाता है कि किसी राष्ट्र की आत्मा को केवल पत्थरों को तोड़कर समाप्त नहीं किया जा सकता। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आधुनिक सुविधाओं और भव्य स्थापत्य ने इसकी गरिमा को और बढ़ाया है। साथ ही यह मंदिर भारत को यह स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति ने हर संकट के बाद स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता दिखाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई बार यह कहा है कि विकास और विरासत साथ-साथ चल सकते हैं। यही कारण है कि सरकार ने एक ओर आधुनिक आधारभूत संरचना पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिरों, तीर्थों और सांस्कृतिक केंद्रों के संरक्षण को भी महत्व दिया। सोमनाथ मंदिर परिसर का आधुनिकीकरण, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और आसपास के क्षेत्र का विकास इसी दृष्टि का हिस्सा है। हालांकि, इस अवसर पर यह भी आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित न रह जाए। मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के साथ-साथ देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी समान गंभीरता से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय गौरव तभी सार्थक होगा, जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भारत की उस अटूट चेतना का प्रमाण हैं, जिसने सदियों के संघर्ष के बाद भी अपनी पहचान को जीवित रखा। यह अवसर केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की सांस्कृतिक दिशा तय करने का भी है। यदि विरासत और विकास का संतुलन बना रहा, तो भारत विश्व मंच पर अपनी सभ्यतागत शक्ति के रूप में और अधिक मजबूती से उभरेगा। आज जब भारत विश्व मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है, तब सोमनाथ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र देश की सांस्कृतिक शक्ति को मजबूत करते हैं।

जम्मू-कश्मीर: 17 लाख कनाल से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

जम्मू, एजेंसी।

जम्मू कश्मीर में भूमाफियाओं द्वारा 17 लाख कनाल से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें जम्मू संभाग की हिस्सेदारी 14 लाख कनाल से अधिक है। वहीं, प्रदेश के सभी 20 जिलों में राजौरी जिला इस सूची में शीर्ष पर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है।

एक कनाल, एक एकड़ का आठवां हिस्सा (0.125 एकड़) होता है। साथ ही, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 20 मरला मिलकर एक कनाल बनाते हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पूरे जम्मू कश्मीर में राजस्व रिकॉर्ड से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण वाली कुल 17,27,247 कनाल जमीन की अवैध प्रविष्टियों को निरस्त कर दिया गया है। कुल आंकड़ों में से अकेले जम्मू संभाग में 14,00,051 कनाल और पांच मरला सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया, जिनकी प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड से हटा दी गईं। वहीं, कश्मीर संभाग में 3,27,199 कनाल जमीन पर अतिक्रमण दर्ज किया गया। आंकड़ों से क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा अंतर सामने आया है। जम्मू संभाग के सात जिलों में से प्रत्येक में एक लाख कनाल से अधिक जमीन पर अतिक्रमण पाया गया, जबकि राजौरी और रियासी जैसे दो जिलों में यह दो लाख कनाल के आंकड़ा को पार कर गया।

उर्वरक संकट पर सरकार विफल, पीएमप्रणाम योजना निष्प्रभावी : खेड़ा

नई दिल्ली, एजेंसी।

- खेड़ा ने प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों से रासायनिक उर्वरक उपयोग 50 प्रतिशत घटाने को कहना व्यावहारिक नहीं है।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर खरीफ सीजन में 390.54 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता के बावजूद मौजूदा भंडार सिर्फ 51 प्रतिशत मांग को ही पूरा कर पाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि सरकार की पीएमप्रणाम योजना तीन साल पूरे होने के बाद भी निष्प्रभावी साबित हुई है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई पीएमप्रणाम योजना के तहत इस साल तक किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को एक भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। इस कारण कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और किसान अब भी आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हैं।

खेड़ा ने प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों से रासायनिक उर्वरक उपयोग 50 प्रतिशत घटाने को कहना व्यावहारिक नहीं है। किसान अचानक आधी जमीन की खेती बंद नहीं कर सकते और न ही वैकल्पिक प्रणालियों पर तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं, खासकर तब जब सरकार ने अपनी ही योजना को धन और समर्थन से वंचित रखा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि परिवर्तन के लिए योजना, निवेश, वैज्ञानिक सहयोग और संस्थागत प्रतिबद्धता जरूरी है, लेकिन सरकार केवल मीडिया और पीआर अभियानों तक सीमित है। किसान भारत की कार्यबल का 46.1 प्रतिशत हिस्सा हैं और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देती है। ऐसे में यदि सरकार इस अहम वर्ग के लिए गंभीर योजना नहीं बना रही है तो यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार किसके लिए योजना बना रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया युद्ध और वैश्विक संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने, विदेशी यात्राएं टालने, सोने की खरीद कम करने और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और सप्लाई चेन संकट के कारण पूरी दुनिया में ईंधन और उर्वरकों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। केंद्र सरकार देशवासियों पर बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील से देश में गहरे आर्थिक संकट के संकेत : मायावती

लखनऊ, एजेंसी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री की मितव्ययिता की अपील दर्शाती है कि भारत में उत्पन्न संकट केवल पेट्रोलियम उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक संकट है, जो और गहरा होने जा रहा है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस अपील का उल्लेख किया, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देशवासियों से संयम बरतने और ऊर्जा संसाधनों के समझदारीपूर्ण उपयोग की बात कही गई थी।

मायावती ने कहा, यह स्पष्ट करता है कि देश में संकट केवल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसे ईंधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट और गहराने वाला है।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति पहले से ही करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है और आगे इसके जारी रहने की गंभीर आशंका है। बसपा प्रमुख ने कहा, कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव झेल चुके लगभग 100 करोड़ नागरिक अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, न ही और अधिक संयम की गुंजाइश है। इन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकारों को गरीब और मेहनतकश परिवारों को राहत देने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे कदम जनता और देश—दोनों के हित में होंगे और यह आम जनभावना को भी दर्शाते हैं।

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक रैली में ऊर्जा संरक्षण और विदेशी मुद्रा बचत के लिए कई सुझाव दिए थे।

उन्होंने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, शहरी क्षेत्रों में मेट्रो के उपयोग, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल, पार्सल परिवहन के लिए रेलवे के उपयोग और 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देने की बात कही थी।

मोदी ने यह भी कहा था कि देश को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने की खरीद और विदेश यात्रा को एक वर्ष तक टालने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनाए गए डिजिटल माध्यमों - 'वर्क फ्रॉम होम', 'वर्चुअल मीटिंग' और 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' को फिर से अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

मोदी की विदेश यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से करेंगे जहां यूएई से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अहम समझौते होने की संभावना है जबकि नॉर्डिक देशों के साथ स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित प्रौद्योगिकी के बारे में महत्वपूर्ण साझीदारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री की आगामी पांच देशों की यात्रा के बारे में कहा, ₹प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे पर निकल रहे हैं। उनके कार्यक्रम का पहला पड़ाव यूएई होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूएई के साथ हमारे बहुआयामी संबंध हैं।

अन्नाद्रमुक विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगी: कृष्णमूर्ति

चेन्नई, एजेंसी।

ऑल इंडिया अन्नाब द्रविड़ मुन्नेलत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने 13 मई को प्रस्तावित विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अग्री एस एस कृष्णमूर्ति ने चेन्नई में मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि संभावित 'क्रॉस वोटिंग' पर कानूनी परिणाम का सामना करना होगा।

ओ एस मणियन और ई के पलानीस्वामी समर्थक गुट के अन्य विधायकों के साथ कृष्णमूर्ति ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्णय पार्टी के महासचिव द्वारा लिया गया है।

कृष्णमूर्ति ने कहा, ''महासचिव ने फैसला किया है कि अन्नाद्रमुक कल विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगी।

उन्होंने कहा कि सभी पार्टी विधायकों को औपचारिक रूप से निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है।

संभावित 'क्रॉस-वोटिंग' या प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से किसी भी नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नेता ने कानूनी परिणामों की कड़ी चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि यदि आवश्यक हुआ तो दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

सार समाचार

इनामी महिला माओवादी बेला गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। झारखंड में सक्रिय 15 लाख रुपये की इनामी महिला माओवादी श्रद्धा विश्वास उर्फ बेला को कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे उसके गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बेला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चाकदह इलाके की निवासी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा विश्वास लंबे समय से माओवादी संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। उसके खिलाफ झारखंड के अलग-अलग थानों में लगभग 23 मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था और कई एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं।

गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद और एसटीएफ प्रमुख सीबी सोलोमन ने कार्रवाई की जानकारी साझा की।

यमुना नदी में छह लोग डूबे, चार की मौत व दो को बचाया गया

आगरा , एजेंसी। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को यमुना नदी में नहाने के दौरान छह लोग डूब गए। रेस्क्यू के दौरान दो लोगों को बचालिया गया लेकिन चार लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है।

बताया गया कि सोमवार की शाम आगरा के विद्यापुरम फाउंड्री नगर निवासी सौरभ पुत्र भूरी सिंह नाई की पुत्री नित्या (एक वर्ष) के जन्मदिन का कार्यक्रम था। इस बर्थडे पार्टी में कुछ रिश्तेदार बाहर से आए थे।

मंगलवार को सभी यमुना नदी नहाने गये। नहाने के दौरान दोहपर करीब एक बजे दोपहर थाना क्षेत्र कमला नगर अंतर्गत यमुना नदी के बल्केश्वर घाट पर दो बच्चे नदी की गहराई की ओर जाने लगे और डूबने लगे।

बच्चों को बचाने गए अन्य लोग भी डूबने लगे। देखते ही देखते कान्हा (22) पुत्र रिंकू, महक (19) पुत्री कालीचरण निवासीगण ग्राम कुंजनपुर थाना सादाबाद हाथरस, रिया उम्र (17) पुत्री मनोज निवासी तारसी मथुरा, विक्की (11) पुत्र राकेश, काजल (17) पुत्री भूरी सिंह निवासी विद्यापुरम फाउंड्री नगर और अंशु (13) पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम कुंजनपुर थाना सादाबाद हाथरस डूब गये।

नीट-यूजी परीक्षा रद्द होना छात्रों के विश्वास पर बड़ा आघात: नवीन पटनायक

भुवनेश्वर, एजेंसी।

ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि नीट-यूजी रद्द किया जाना परीक्षा प्रणाली के प्रति विद्यार्थियों के विश्वास पर गंभीर आघात है।

प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को तीन मई को आयोजित वर्ष 2026 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) को रद्द कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार ने कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष पटनायक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, जब परीक्षाओं की शुचिता से समझौता होता है, तो यह केवल एक चूक नहीं बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अनुशासन के साथ पढ़ाई की, सुख-सुविधाओं का त्याग किया और तैयारी के लिए रातों की नींद गंवाई। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है जब नीट का प्रश्नपत्र लीक हुआ है। ऐसी घटनाएं विद्यार्थियों में अविश्वास और चिंता बढ़ाती हैं तथा निष्पक्षता की उम्मीद रखने वाले मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालती हैं।

आआपा ने पंजाब को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा : चुघ

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब जांच की आंच सीधे विजिलेंस मुख्यालय तक पहुंच गई है।

चुघ ने कहा कि सीबीआई द्वारा पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मुख्यालय को सील करना इस बात का प्रमाण है कि मान सरकार भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। चुघ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि पहले ईडी ने एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिससे पंजाब का सिर शर्म से झुक गया था।

लापरवाह अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे: विजय चौधरी

पटना, एजेंसी।

बिहार में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

एक दिन पहले सरकार द्वारा 'सहयोग' पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 शुरू किए जाने के बाद मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं और यह व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री शीला कुमारी मंडल ने लोगों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान चौधरी ने कहा कि सरकार पहले से जनसुनवाई कार्यक्रम चलाती रही है और अब इसे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जदयू कार्यालय में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जहां आम लोग सीधे अपनी समस्याएं रख सकेंगे।

सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए 'सहयोग' पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अथवा स्वतः निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन सेवा सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक संचालित होगी।

जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना कम खरीदने और तेल बचाने की अपील का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ा विषय है और प्रधानमंत्री ने लोगों को सुझाव दिया है, कोई आदेश नहीं। राज्य के विकास भवन में शराब की बोतल मिलने के मामले पर उपमुख्यमंत्री ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू है और शराब रखने या पीने, दोनों मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।

जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर केंद्र पर बरसी सैलजा

चंडीगढ़, एजेंसी।

कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने मंगलवार को कहा कि लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं और फिर भी केंद्र सरकार समाधान पेश करने के बजाय बार-बार उनसे त्याग और समझौता करने को कह रही है। सैलजा ने यहां जारी एक बयान में दावा किया कि इस तरह की बार-बार की अपीलें इस बात का संकेत देती हैं कि सरकार आर्थिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है।

सिरसा की सांसद सैलजा ने कहा कि कभी लोगों को पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है, तो कभी घरेलू खर्चों में कटौती करने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन्हें दैनिक आवश्यकताओं में भी कटौती करने को कहा जाता है।

उन्होंने दावा किया, ये बार-बार की जाने वाली अपीलें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।₹

कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि नागरिकों को राहत प्रदान करना, स्थिर आर्थिक वातावरण बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। सैलजा ने इस महीने की शुरुआत में आयोजित नीट-स्नातक परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-स्नातक-2026' को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने सीबीआई को इन 'अनियमितताओं' की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया।

कुमारी सैलजा ने कहा, ''नीट 2026 के कथित पेपर लीक की खबरें देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य और मेहनत पर सीधा हमला हैं।

बड़ा मंगल सेवा एवं समरसता का पर्व : कृष्ण गोपाल

लखनऊ, एजेंसी। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल की परम्परा वर्षों पुरानी है। 'बड़ा मंगल' की पावन परम्परा की दिव्यता की अनुभूति करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल मंगलवार को लखनऊ आये। पर्यावरण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक गोपाल आर्य,अवध प्रान्त के प्रान्त प्रचारक कौशल और मंगलमान की टीम के साथ सह सरकार्यवाह ने लखनऊ के अलग—अलग स्थानों पर चल रहे भण्डारे में शामिल हुए। सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल सबसे पहले सदर स्थित गोस्वामी तुलसी दास मंदिर में आयोजित सुन्दर काण्ड पाठ व आरती में शामिल हुए।

फगवाड़ा में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी

फगवाड़ा,एजेंसी।

पंजाब में फगवाड़ा नगर निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा शुरू की गयी अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों की लंबित मांगों के समर्थन में चल रहे इस आंदोलन के कारण शहर की कई नागरिक सेवाएं प्रभावित रहीं। यह आंदोलन जॉइंट पब्लिक एक्शन फ्रंट पंजाब और पंजाब एवं नगर पालिका सफाई कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले चलाया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम कार्यालय फगवाड़ा के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।

हड़ताल के कारण नगर निगम कार्यालयों का कामकाज काफी हद तक ठप रहा, जबकि सफाई व्यवस्था, सीवरेज रखरखाव और अन्य नियमित सेवाएं प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि नगर निकायों के कर्मचारी शहरी ढांचे और जनसेवाओं को बनाये रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत से किया जाना चाहिए। विधायक बलविंदर सिंह ढालीवाल ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

देश में एक हजार की आबादी पर 1.9 नर्स कार्यरत

उदयपुर,एजेंसी।

राजस्थान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में हर एक हजार की जनसंख्या पर करीब 1.9 नर्स कार्यरत है। यह जानकारी मंगलवार को यहां पारस हेल्थ के निदेशक डॉ प्रसून कुमार ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम.. हमारी नर्सें, हमारा भविष्य. ₹सशक्त संदेश जीवन बचाओ₹ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के बताए गए हर एक हजार की आबादी पर तीन नर्स के मानदंड से कम हैं।

रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नर्सिंग शिक्षा, कार्यबल प्रतिधारण और व्यावसायिक विकास में लगातार निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नर्सें किसी भी स्वास्थ्य संस्थान की रीढ़ और मरीज की देखभाल की मुख्य स्तंभ होती हैं। उनकी हमदर्दी, समर्पण और बिना थके सेवा हर दिन मरीजों और परिवारों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लाती है।

इस अवसर पर पारस हेल्थ के चिकित्सा अधीक्षक डॉ राम कुमार बांग ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बढ़ती मुश्किलों और मरीजों की बढ़ती उम्मीदों के साथ नर्सों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

एलडीएफ ने केरल मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में देरी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की

केरलम में मुख्यमंत्री चुनने में देरी पर सियासी घमासान

तिरुवनंतपुरम (केरल), एजेंसी।

केरल में विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने मंगलवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के चयन में देरी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) पर हमला बोला और आरोप लगाया कि गठबंधन जनादेश का सम्मान करने में ₹विफल₹ रहा है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता एवं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) संयोजक टी. पी. रामकृष्णन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ₹कांग्रेस और यूडीएफ को जनादेश का सम्मान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यहां एलडीएफ की बैठक में भाग लेने के बाद कहा, ₹राज्य की जनता ने सरकार बनाने के लिए यूडीएफ के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस और यूडीएफ का नैतिक दायित्व है कि वे बदले में उनके साथ न्याय करें। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार के गठन से पहले ही वे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थीं जो सामान्यतः शासन का हिस्सा होनी चाहिए। रामकृष्णन ने दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों का तबादला संगठन के पदाधिकारियों द्वारा तैयार की गई सूचियों के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के औपचारिक गठन से पहले ही उठाए गए ऐसे कदम लोकतांत्रिक प्रथाओं के अनुरूप नहीं थे।

उन्होंने सप्लाईको डिपो के माध्यम से चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों का हवाला देते हुए, यूडीएफ पर जनविरोधी कदम उठाने का भी आरोप लगाया । रामकृष्णन ने कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार ने 13 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं की थी और बाद में कीमतों में संशोधन केवल कैबिनेट के निर्णय के बाद ही किया गया था। उन्होंने कहा, अब खबरें आ रही हैं कि सप्लाईको डिपो के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल की कीमत में दो रुपये की वृद्धि की गई है। यह कदम बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एलडीएफ विकास और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए नयी सरकार को पूरा समर्थन देगा और सभी जायज मुद्दों पर सहयोग करेगा। रामकृष्णन ने मुख्यमंत्री के चुने जाने से पहले विपक्ष के नेता का चयन करने की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने पूछा, पहले सरकार का गठन होना चाहिए। मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष के नेता का चयन करने में क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि शासन का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री का चयन करना नहीं है, बल्कि मंत्रियों का चयन करना और विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करना भी है।

उन्होंने कहा, यह देरी एक गलत प्रथा है जिसकी आलोचना होनी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर एलडीएफ की अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए रामकृष्णन ने कहा कि इस मामले में कोई देरी या विवाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि माकपा के पोलित ब्यूरो ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का जिम्मा पार्टी की राज्य इकाई को सौंपा है।

रामकृष्णन ने यहां मीडिया से कहा, विपक्षी नेता के चयन को लेकर कोई विवाद नहीं है।

सार समाचार

हरियाणा बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एचबीएसई) के मंगलवार को 12वीं कक्षा के घोषित परिणामों में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं ने एक बार फिर छात्रों को पीछे छोड़ दिया। बोर्ड मुख्यालय भिवानी में आयोजित प्रेस वार्ता में बोर्ड अध्यक्ष डॉ पवन कुमार ने परीक्षा परिणाम जारी किये। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा में कुल दो लाख 42 हजार 856 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से दो लाख पांच हजार 618 विद्यार्थी सफल रहे। परीक्षा परिणाम 84.67 प्रतिशत दर्ज किया गया। छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97 प्रतिशत रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 81.45 प्रतिशत रहा। इस तरह लड़कियों ने लड़कों से 6.52 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया। जिलावार प्रदर्शन में चरखी दादरी पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, जबकि नूंह जिला सबसे नीचे रहा।

तमिलनाडु में कार-ट्रक की टक्कर में परिवार के चार लोगों की मौत

चेन्नई,एजेंसी। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पोलाची-पल्लादम मेन रोड पर एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए उनके परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये देने का ऐलान किया। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि सलेम जिले के कडायमपट्टी गांव के रहने वाले 37 वर्षीय धनपाल और उनके परिवार के चार सदस्य एक क्रूजर कार में पल्लादम से पोलाची जा रहे थे, तभी पल्लादम से उल्टी दिशा में पोलाची की ओर जा रहे एक सामान से भरे ट्रक से उनकी कार टकरा गई। ट्रक ड्राइवर 39 वर्षीय सरवनन तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। जिससे दुर्घटना हुई और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में धनपाल, उनकी 35 वर्षीया पत्नी मेनका, उनकी 17 वर्षीया बेटी कनिष्का और मेनका की बहन की 23 वर्षीया बेटी स्नेहा शामिल हैं।

मोहाली विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर पर सीबीआई की छापा

चंडीगढ़, एजेंसी।

- कथित रिश्वतखोरी मामले में विजिलेंस प्रमुख के रीडर ओपी राणा समेत बिचौलियों राघव गोयल और उनके पिता विकास गोयल को गिरफ्तार किया गया।

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार देर रात पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली स्थित दफ्तर पर छापा मारा। इस दौरान कथित रिश्वतखोरी मामले में विजिलेंस प्रमुख के रीडर ओपी राणा समेत बिचौलियों राघव गोयल और उनके पिता विकास गोयल को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि ये लोग एक मामले को निपटाने के लिए 20 लाख रुपये की सौदा कर रहे थे। सीबीआई ने चंडीगढ़ के एक पांच सितारा होटल में जाल बिछाकर कार्रवाई की, जहां कथित तौर पर शिकायतकर्ता के साथ सौदेबाजी चल रही थी।

सीबीआई टीम ने मलोट स्थित गोयल परिवार के घर पर भी छापा मारा, जहां से कुछ दस्तावेज और करीब पांच लाख रुपये नकद बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि राघव गोयल भाजपा से जुड़े एक प्रमुख नेता हैं। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। वहीं विजिलेंस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के फरार होने और फोन न उठाने की भी जानकारी सामने आई है।

पंजाब के इतिहास में यह पहली बार माना जा रहा है जब किसी राज्य जांच एजेंसी के दफ्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों में केंद्रीय एजेंसी ने छापा मारा हो। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गईं। पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक उजागर हो रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने इसे चुनावों से पहले लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। मजीठिया ने कथित रिश्वत मामले में हुई कार्रवाई को लेकर एक्स पर कहा, ₹पंजाब में भ्रष्टाचार अब ऊपर से नीचे तक परत-दर-परत उजागर हो रहा है। कथित 20 लाख रुपये की रिश्वत डील जांच के घेरे में है और केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान 13 लाख रुपये बरामद किए हैं।₹ उन्होंने कहा, ₹पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पर बीती रात एक केंद्रीय एजेंसी ने छापा मारा।

क्या आप हैरान हैं? मैं नहीं हूं।₹ उन्होंने आरोप लगाया कि यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तय कार्यप्रणाली बन चुकी है। पहले केंद्रीय एजेंसियां नेताओं को निशाना बनाती हैं, फिर नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करती हैं, ताकि संदेश दिया जा सके कि लाइन में लगो या परिणाम भुगतो। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव नजदीक हैं, इसलिए यह लोकतंत्र पर एक और हमला है। आने वाले समय में कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य की राजनीति में इसी तरह का रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस इस दौरान सबसे बड़ी पीड़ित रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया, डराया गया और परेशान किया गया। कई मामलों को बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, हम भूले नहीं हैं और न ही भूलेंगे लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। यह तानाशाही है।

पंजाब में पंजाबी की अनदेखी बर्दाश्त नहीं: प्रो. ख्याला

अमृतसर, एजेंसी।

पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रो सरचांद सिंह ख्याला ने मंगलवार को राज्य के सीबीएसई से संबद्ध आर्मी पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा की अनदेखी को गंभीर चिंता का विषय करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में पंजाबी को हाशिए पर धकेलना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहां जारी बयान में प्रो. ख्याला ने कहा कि सीबीएसई और संबंधित अधिकारियों को पंजाब की भाषाई संवेदनशीलता और संवैधानिक वास्तविकता का पूरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर स्कूल में पंजाबी पढ़ाये जाने संबंधी 'पंजाब और अन्य भाषाओं की शिक्षा अधिनियम, 2008' का सख्ती से पालन होना चाहिए।

इस कानून के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देने के बजाय संवाद और सहमति से हल किया जाना चाहिए, न कि किसी थोपे गये फैसले से। प्रो. ख्याला ने कहा कि भाजपा पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। पंजाबी गुरु साहिबानों, शहीदों और लोक-संस्कृति की भाषा है। इसे कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाबी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा, संस्कृति, इतिहास और साझा विरासत की पहचान है। पंजाब की धरती पर पंजाबी को उसका सम्मान और संवैधानिक दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए।

प्रो. ख्याला ने कहा कि संस्कृत सीखना या सिखाना गलत नहीं है, लेकिन यह पंजाबी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख गुरु साहिबानों ने गुरबाणी लोक-भाषा में रचकर जनभाषाओं को सम्मान दिया।

उन्होंने नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2020 में लागू की गयी नयी शिक्षा नीति (एनईपी-2020) की सराहना करते हुए कहा कि यह शिक्षा को अधिक लचीला, कौशल आधारित, मातृभाषा केंद्रित और वैश्विक स्तर का बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति में कम से कम पांचवीं कक्षा तक और संभव हो तो आठवीं तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है।

रांची में वर्षों से चल रहा 'बिहार आई बैंक ट्रस्ट', अब बदलेगा नाम

रांची,एजेंसी।

झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के सहयोग से वर्षों से संचालित 'बिहार आई बैंक ट्रस्ट' का नाम अब आखिरकार बदल दिया जाएगा। राज्य गठन के बाद भी पुराने नाम से चल रहे इस संस्थान को जल्द ही 'झारखंड आई बैंक' के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

लोकभवन में आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में राज्यपाल ने कहा कि संस्थान को राज्य में एक उत्कृष्ट और विश्वसनीय नेत्र चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके। राज्यपाल ने ट्रस्ट से जुड़ी भूमि संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ऐसा सेवा और कार्य मॉडल विकसित करे, जिससे उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसके जरिए आधुनिक और उन्नत नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।

उन्होंने विशेष रूप से एडवांस आई केयर सुविधाओं के विकास पर बल दिया। बैठक में राज्यपाल ने ट्रस्ट को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्देश भी दिया।

कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे: कंग

शहीद भगत सिंह नगर,एजेंसी। लोकसभा सदस्य मलविंदर सिंह कंग ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी बिना देरी या भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। जिला प्रशासनिक परिसर में आयोजित तिमाही समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद ने जिले में लागू विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वांगीण विकास और जमीनी स्तर पर जनसेवाओं की मजबूत डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में उनके साथ जिला उपायुक्त गुलप्रीत सिंह औलख भी मौजूद रहे।

सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी योजनाओं की नियमित निगरानी की जाये और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाये रखी जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी सक्रिय भूमिका निभायें।

दुनिया में एरी कोकून का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मेघालय: संगमा

शिलांग, एजेंसी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सोमवार को री-भोई जिले के भोइरिम्बोंग में एरी रेशम धागा निर्माण इकाई 'साई लुम' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि मेघालय दुनिया में एरी कोकून का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ सालाना लगभग 700 टन कोकून का उत्पादन होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एरी कोकून से रेशम का धागा बनने की प्रक्रिया के बीच जो तकनीकी अंतर था, वह अब तक राज्य की रेशम मूल्य श्रृंखला की सबसे बड़ी बाधा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी उत्पादन के बावजूद, स्थानीय स्तर पर कताई सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपने कोकून कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर, बुनकरों को वही धागा ऊंची कीमतों पर वापस खरीदना पड़ता था। श्री संगमा ने विश्वास व्यक्त किया कि 'साई लुम' जैसे नए उद्यम कोकून और धागा उत्पादन के बीच की इस खाई को पाटेंगे। री-भोई जिला वर्तमान में राज्य में रेशम उत्पादन का मुख्य केंद्र है, जहाँ लगभग 7,900 रेशमकीट पालक और 4,760 बुनकर इस कार्य में लगे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 1.20 करोड़ रुपये है, जिसे उद्यमी के निजी निवेश के साथ-साथ 'प्राइम मेघालय' और 'उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान केंद्र' (नेक्टर) के सहयोग से विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि अब तक मेहनत के हिसाब से हितधारकों को उचित मुनाफा नहीं मिल सका है, इसलिए सरकार इस क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस नई इकाई की कताई क्षमता प्रतिदिन 25-30 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले एरी धागे की है, जिससे सालाना लगभग 7.5 टन धागे का उत्पादन संभव होगा।

एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह इकाई स्थानीय किसानों से सीधे उचित और स्थिर कीमतों पर एरी कोकून खरीदेगी, जिससे किसानों की बाजार संबंधी अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी।

नीट परीक्षा रद्द होने के मामले में यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

नैनीताल, एजेंसी।

उत्तराखंड में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने नीट यूजी परीक्षा रद्द होने को करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ क्रूर मजाक करार देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि 23 लाख छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य पर सीधा प्रहार है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को कहा कि पर्वतीय राज्य सहित पूरे देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले यह साबित करते हैं कि भाजपा सरकारें युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, इच्छाशक्ति और जवाबदेही नहीं बची है कि एक सामान्य परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। आर्य ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने सरकार की नीति और नीयत दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

हर बार दिखावटी जांच, बड़ी घोषणाएं और खोखले आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन परिणाम शून्य रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार को औपचारिकताओं से बाहर निकलकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह सवाल स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या वह देश के युवाओं के साथ न्याय कर रही है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने के कारण अब 23 लाख छात्र दोबारा परीक्षा देने को मजबूर होंगे और देश के 552 शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों तक फिर यात्रा करेंगे।

इससे करोड़ों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल की अतिरिक्त खपत होगी तथा छात्रों और अभिभावकों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश का युवा अब जवाब मांग रहा है कि आखिर कब तक उनके सपनों को पेपर लीक माफिया और सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी।

पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने कारोबारी से 15 लाख रुपये लूटे

सोनीपत,एजेंसी। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने पानीपत के एक बैटरी कारोबारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश जांच का बहाना बनाकर कारोबारी की कार रुकवाने के बाद उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर गए और कार में रखा कैश एवं मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पानीपत निवासी बैटरी कारोबारी किसी काम से सोनीपत आया हुआ था। जब वह बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के पास जीटी रोड से गुजर रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पुलिसकर्मी बनकर उसकी कार रुकवाई। दोनों युवक पुलिस की वर्दी में थे, जिससे कारोबारी को उन पर शक नहीं हुआ।

पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए जांच की बात कही।

राज ठाकरे ने व्यक्तिगत खर्च कम करने की अपील पर पीएम मोदी पर साधा निशाना

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने नागरिकों से व्यक्तिगत खर्च कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित अपील को लेकर उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि जब राजनीतिक नेता महंगे सार्वजनिक कार्यक्रमों, काफिलों तथा विदेशी दौरों को जारी रखे हुये हैं, तो आम लोगों को अपने खर्चों में कटौती करने की सलाह क्यों दी जा रही है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि जहां नागरिकों से ईंधन, यात्रा और सोने की खरीद जैसे खर्चों में कटौती करने का आग्रह किया जा रहा है।

वहीं राजनीतिक रोड-शो, जनकल्याणकारी योजनाओं और चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर भारी सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है। उन्होंने मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और कथित आर्थिक अनिश्चितता पर भी चिंता जतायी और देश की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा करने के लिये संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मनसे प्रमुख ने सरकार पर आर्थिक अनुशासन को लेकर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया और पिछले नेतृत्व के उदाहरण देते हुये तर्क दिया कि जनता को मितव्ययिता की सलाह देने से पहले राजनीतिक नेताओं को अपने खर्च कम करने चाहिए। उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भी जिक्र किया और कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भी कच्चा तेल 90 से 100 अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन उनके अनुसार, तब वित्तीय बोझ जनता पर इस तरह नहीं डाला गया था।

सरकार पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि जहां एक ओर रेवड़ी संस्कृति या लोकलुभावन कल्याणकारी राजनीति की सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक लाभ के लिये कल्याणकारी और चुनावी योजनाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। मनसे नेता ने अपनी टिप्पणियों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में भी चिंताएं व्यक्त कीं। राज ठाकरे ने दावा किया कि भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है और आरोप लगाया कि बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक देश से दूर जा रहे हैं।

उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के तीन गवर्नरों के इस्तीफे का उल्लेख करते हुये अर्थव्यवस्था की समग्र दिशा और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाये।

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि नागरिकों को व्यक्तिगत खर्च कम करने की सलाह देने से पहले वे सरकारी खर्च और विदेशी दौरों में कटौती करें। मनसे प्रमुख ने देश की आर्थिक स्थिति और संबंधित नीतिगत चिंताओं पर विस्तृत चर्चा के लिये संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का केंद्र पर हमला, महंगाई एवं नीतियों पर उठाए सवाल

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया अपीलों ने जनता की समस्याओं को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। बैज ने कहा कि देश पहले से ही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति संकट और महंगाई की मार से जूझ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से की गई सलाहें आम जनता की परेशानियों को और बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों से उर्वरक उपयोग कम करने, कामकाजी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने, महिलाओं को खाद्य तेल और गैस का कम उपयोग करने, सोना न खरीदने तथा विदेश यात्रा से बचने जैसी सलाहें व्यवहारिक नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उर्वरक की कमी के कारण किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

1.01 करोड़ रुपये नकद, एके-47 समेत भारी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक बरामद

नारायणपुर में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार

नारायणपुर,एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में चलाए जा रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत नारायणपुर पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों द्वारा जंगलों में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 1.01 करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने यह जानकारी मंगलवार को दी।

पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग और मजबूत आसूचना तंत्र की मदद से यह कार्रवाई संभव हो सकी। पिछले एक महीने से जिले के संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में लगातार सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई छिपे डंप खोज निकाले, जहां से अत्याधुनिक हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर, वायरलेस सेट, बैटरी और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। संयुक्त टीम ने कुल 1,01,64,000 रुपये नकद जब्त किया है, जिसे नक्सल संगठन के लॉजिस्टिक और नेटवर्क संचालन में इस्तेमाल किया जाना था।

संयुक्त कार्रवाई के दौरान तीन एके-47 राइफल, तीन एसएलआर राइफल, दो .303 राइफल, एक .315 राइफल, दो बारह बोर बंदूक और दो देशी कट्टे बरामद किए गए। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में जिंदा कारतूस, मैगजीन और बीजीएल सेल भी जब्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 132 बीजीएल सेल, आठ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, छह बंडल कॉर्डेक्स वायर, वॉकी-टॉकी सेट, मोटोरोला वायरलेस सेट, बिजली वायर, रेडियो सेल और संदिग्ध विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से नक्सलियों की हथियार आपूर्ति और आईईडी निर्माण क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अब तक जिले में कुल 270 हथियारों की रिकवरी हो चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि क्षेत्र में शांति, विकास और सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुलिस ने आम नागरिकों और ग्रामीणों से अपील की है कि जंगलों या आसपास के क्षेत्रों में किसी भी संदिग्ध वस्तु, हथियार या विस्फोटक सामग्री की जानकारी तुरंत पुलिस और सुरक्षा बलों को दें। अधिकारियों का कहना है कि अबूझमाड़ के जंगलों में अभी भी नक्सलियों द्वारा छिपाई गई सामग्री मिलने की संभावना बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार चल रही संयुक्त कार्रवाइयों और जनसहयोग के कारण नारायणपुर जिले में नक्सली गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं और क्षेत्र धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

अल्पसंख्यक स्कूलों में टीईटी की अनिवार्यता नहीं, शिक्षा अधिकारियों को दी चेतावनी

छत्रपति संभाजीनगर,एजेंसी। बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने दोहराया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है पिछले न्यायिक निर्देशों के बावजूद टीईटी पास न होने के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावों को बार-बार खारिज किया गया है जो उचित रवैया नहीं है।

अदालत ने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर ऐसी गलतियां दोहरायी गयीं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए न्यायमूर्ति विभा कंकणवाड़ी और न्यायमूर्ति अजीत बी. कड़ेठाणकर की खंडपीठ ने तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अदालत ने 'शिक्षण सेवक' के रूप में नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा अधिकारी के पारित अस्वीकृति आदेशों को रद्द कर दिया। ये याचिकाएं सैयद अबू जैद सैयद रफीक और एक अन्य याचिकाकर्ता, गायकवाड़ सायली व्यंकटेश और साईनाथ गणपत बनसोडे ने दायर की थीं। इन तीनों मामलों में शिक्षा विभाग ने इस आधार पर नियुक्तियों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। उच्च न्यायालय में कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता सैयद तौसीफ यासीन ने सैयद अबू जैद और एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता शेख तारिक मोबिन एच ने गायकवाड़ सायली व्यंकटेश का और अधिवक्ता केपी रॉज ने साईनाथ गणपत बनसोडे की ओर से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संबंधित स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान थे, इसलिए उन पर टीईटी की शर्त उसी तरह लागू नहीं की जा सकती।

प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पा लिया है।

रायपुर,एजेंसी। प्लेऑफ़ का रास्ता अब मुश्किल होता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, और रायपुर की तेज गर्मी में, दो ऐसी टीमें जिनकी अब तक की यात्रा बिल्कुल अलग रही है, एक ऐसी टक्कर के लिए तैयार हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग में उनके पूरे सीजन का भविष्य तय कर सकती है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के ज़्यादातर हिस्से में एक ऐसी टीम की तरह दिखी है जो पूरी तरह से नियंत्रण में है। शांत, संयमित और खतरनाक, उन्होंने 11 मैचों में सात जीत के साथ धीरे-धीरे अपनी लय बनाई है और अब वे एक और बार प्लेऑफ़ में पहुँचने की कगार पर खड़े हैं।

लेकिन उनके सामने एक ऐसी टीम आ रही है जिसने ठीक सही समय पर अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पा लिया है- एक नई ऊर्जा से भरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिसने खुद को टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार से खींचकर वापस मुकाबले में ला खड़ा किया है। जब बुधवार की रात ये दोनों टीमें शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरेंगी, तो दाँव पर सिर्फ़ दो अंक ही नहीं होंगे। बल्कि दाँव पर होगी टीम की लय, आत्मविश्वास और शायद पूरे अभियान की दिशा।

आरसीबी का यह सीज़न एक बार फिर विराट कोहली की मौजूदगी से ही आगे बढ़ा है। हो सकता है कि अब वह अकेले ही टीम का सारा बोझ न उठाते हों, लेकिन वह अब भी इस बेंगलुरु टीम की भावनात्मक धड़कन बने हुए हैं। उनके बनाए 379 रन पूरी दबंगई और इरादे के साथ आए हैं; उन्होंने पारी की शुरुआत में ही टीम के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है, जिससे उनके आस-पास के दूसरे खिलाड़ियों को भी खुलकर खेलने का मौका मिला है। कप्तान रजत पाटीदार ने पारी के बीच के ओवरों में निडरता का परिचय दिया है; वह क्रीज़ पर आते ही गेंदबाज़ों पर हमला बोल देते हैं।

फिर टीम के पास टिम डेविड जैसा 'फिनिशर' भी है, जिसने पारी के आखिरी ओवरों को विपक्षी गेंदबाज़ों के लिए पूरी तरह से अफरा-तफरी और मुश्किलों से भरे पलों में बदल दिया है। और जब पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ़ हालात मुश्किल हो गए थे तो क्रुणाल पांड्या ही थे जिन्होंने एक ऐसी जुझारू और दमदार पारी खेली, जिसकी ज़रूरत अक्सर चैंपियन टीमों को होती है। मांसपेशियों में खिंचाव, दबाव और लड़खड़ाती हुई रन-चेज़ जैसी तमाम मुश्किलों से जूझते हुए, उन्होंने 46 गेंदों में 73 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आरसीबी को जीत दिलाई।

गेंदबाज़ी के मोर्चे पर, हमेशा की तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर अपने पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी है। इस सीज़न में उनके द्वारा लिए गए 21 विकेट एक ऐसे गेंदबाज़ की कहानी बयाँ करते हैं, जो आज भी लय, गेंद की मूवमेंट और नियंत्रण को ज़्यादातर दूसरे गेंदबाज़ों के मुकाबले कहीं बेहतर समझता है। लेकिन जहाँ आरसीबी का प्रदर्शन लगातार एक जैसा और स्थिर रहा है, वहीं केकेआर का सफ़र उतार-चढ़ावों और नाटकीयता से भरा रहा है।

आईपीएल 2026: सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से रौंदकर 'नंबर-1' बनी गुजरात टाइटंस

अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस (जीटी) ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 56वें मुकाबले को 82 रन से अपने नाम किया। इस जीत के साथ जीटी ने 16 अंकों के साथ शीर्ष स्थान अपने नाम कर लिया है। गुजरात टाइटंस 12 मुकाबलों में 8 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 12 मुकाबलों में पांचवीं हार के बाद तीसरे पायदान पर है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। जीटी को महज 26 के स्कोर तक दो झटके लग गए थे। इसके बाद साईं सुदर्शन ने निशांत संधु के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की।

संधु 14 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद साईं सुदर्शन ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ चौथे विकेट के लिए 41 गेंदों में 60 रन जोड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। सुदर्शन 44 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 61 रन बनाकर आउट हुए। यहां से वॉशिंगटन ने जेसन होल्डर के साथ पांचवें विकेट के लिए 40 रन जुटाए। वॉशिंगटन 33 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए। विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट निकाले। पैट कमिंस के नाम 1 विकेट रहा।

इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 14.5 ओवरों में महज 86 रन पर सिमट गई। इस टीम को पारी की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड (0) के रूप में बड़ा झटका लग गया था। उस समय तक टीम का खाता भी नहीं खुल सका था।

इसके बाद टीम ने 6 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (6) का विकेट भी गंवा दिया।यहां से ईशान किशन (11) ने स्मरण रविचंद्रन (9) के साथ तीसरे विकेट के लिए 17 रन जुटाए। हेनरिक क्लासेन (14) ने सलिल अरोड़ा के साथ पांचवें विकेट के लिए 23 गेंदों में 24 रन जोड़े, लेकिन यह साझेदारी टीम को जीत दिलाने के लिए नाकाफी थी। सलिल ने टीम के खाते में 16 रन का योगदान दिया, जबकि पैट कमिंस ने 19 रन जोड़े। विजेता टीम की तरफ से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट हाथ लगे। मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने 1-1 विकेट निकाला।

ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे स्थान पर पहुंचे केएल राहुल

धर्मशाला,एजेंसी। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल में सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के ख़िलाफ़ सोमवार को बेहद ज़रूरी जीत दर्ज की, जिससे प्लेऑफ़ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें ज़िंदा रहीं। हालांकि 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल वैसा योगदान नहीं दे पाए, जैसा वह चाहते थे। लेकिन 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर वह इस सीजन के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में नंबर 3 से नंबर 2 पर पहुंच गए। उन्होंने अब तक 12 पारियों में 177.98 के स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं।

मंगलवार को सनराइज़र्स हैदराबाद (एसआरएच) का मुकाबला गुजरात टाइटंस (जीटी) से है, इसलिए राहुल की यह पोज़िशन सुरक्षित नहीं है। अभिषेक शर्मा (475) और उनके सबसे पुराने व अच्छे दोस्त शुभमन गिल (462) उनके बेहद क़रीब हैं। वहीं हेनरिक क्लासेन 11 पारियों में 157.32 के स्ट्राइक रेट से 494 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। उनके पास भी अपनी बढ़त को और मजबूत करने का मौक़ा है।

2016 और 2017 में लगातार दो बार पर्पल कैप जीतने वाले भुवनेश्वर कुमार ने साफ़ कर दिया है कि 36 साल की उम्र में भी उनकी कला कम नहीं हुई है, भले ही साल के बड़े हिस्से में वह लगभग नजर नहीं आते हैं।

मैं भारतीय टीम में वापसी के बारे में नहीं सोचता हूं: भुवनेश्वर

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की तरफ से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भुवनेश्वर के प्रदर्शन को देखते हुए हाल ही में पूर्व भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भुवनेश्वर को भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग की थी। हालांकि, भुवनेश्वर ने नेशनल टीम में वापसी की बातों को खारिज कर दिया है। भुवनेश्वर ने कहा कि पिछली निराशाओं से सीखने के बाद अब वह लंबे समय के लक्ष्य तय नहीं करते हैं। आरसीबी की ओर से खेलते हुए भुवनेश्वर इस सीजन में 21 विकेट हासिल कर चुके हैं। भुवनेश्वर पावरप्ले के साथ-साथ डेथ ओवरों में भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं।

आरसीबी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में 36 वर्षीय गेंदबाज ने कहा, मैं भारतीय टीम में वापसी के बारे में नहीं सोचता। कई साल हो गए हैं जब मैंने लंबे समय के लक्ष्य तय करना बंद कर दिया है। इसका कारण यह है कि जब भी मैंने ऐसा किया है, तो यह मेरे लिए कभी काम नहीं आया। आईपीएल में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद हाल ही में कई पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने नेशनल टीम में उनकी वापसी की वकालत की, लेकिन भुवनेश्वर ने कहा कि वह अपने करियर में जहां हैं, उससे खुश हैं।

उन्होंने कहा, मैं खुश हूं कि 200 मैच हैं, इतने सारे विकेट हैं। मुझे लगता है कि यह सब उन कामों का इनाम है जो मैंने इतने वर्षों में किए हैं। अच्छे और बुरे साल भी रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो, इस समय मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है। बेशक, अगर मैं कहूं कि भविष्य में खेलना बंद करने के बाद ऐसा नहीं होगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि ये सब यादें हैं जो बाद में काम आएंगी। हालांकि, इस समय, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत नॉर्मल है।

भुवनेश्वर ने आगे बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका न मिलने से उन्हें अपना वर्कलोड बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिली है, क्योंकि उनके पास रिकवर होने का समय है। उन्होंने कहा, जब से मैंने देश के लिए खेलना बंद किया है, सबसे अच्छी बात यह है कि आईपीएल के बाद मुझे बहुत सारे ब्रेक मिलते हैं। मैं टच में रहने के लिए काफी क्रिकेट खेलता हूं और मुझे दूसरे काम करने के लिए भी काफी समय मिलता है।

चीन ने लगातार 12वीं बार जीता विश्व टीम टेबल टेनिस खिताब

लंदन,एजेंसी। चीन ने वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जापान पर 3-0 से जीत हासिल करते हुए पुरुषों की टीम का लगातार 12वां खिताब अपने नाम किया। यह जीत लियांग जिंगकुन के एक और शानदार वापसी वाले प्रदर्शन की बदौलत मिली। सेमीफाइनल में फ्रांस के एलेक्सिस लेब्रुन के खिलाफ दो गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करने के ठीक एक दिन बाद, लियांग ने जापान के शीर्ष खिलाड़ी टोमोकाज़ु हारिमोटो के खिलाफ भी उसी कारनामे को दोहराया। लियांग को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा; वह शुरुआती दो गेम 11-8 और 11-4 से हार गए, क्योंकि हारिमोटो अपनी ज़बरदस्त गति और आक्रामकता से खेल पर हावी थे।

लेकिन चीनी खिलाड़ी ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल कर ली और निडर होकर आक्रामक खेल खेलते हुए मैच का रुख पलट दिया, और अगले दो गेम 11-9 और 13-11 से जीत लिए। निर्णायक गेम में 8-3 की बढ़त बनाने के बाद हारिमोटो जीत की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन तभी लियांग ने ज़ोरदार वापसी की। हर विनिंग शॉट के बाद ज़ोर से दहाड़ते हुए, लियांग ने लगातार आठ अंक हासिल किए और 11-8 से जीत पूरी करके स्टेडियम में जश्न का माहौल बना दिया। लियांग ने मैच के बाद कहा, कल से आज तक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो।

बिजनेस

देश में बढ़ रहा सोने का आयात

नई दिल्ली,एजेंसी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के नागरिकों से अगले एक वर्ष गैर-जरूरी सोना न खरीदने की अपील की गई है। इसके पीछे की एक वजह सोने का आयात बिल लगातार बढ़ना है, जिसका भुगतान बहुमूल्य विदेशी मुद्रा किया जा रहा है।

भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में 3.48 प्रतिशत रही

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में सालाना आधार पर 3.48 प्रतिशत रही है, जो कि मार्च में 3.40 प्रतिशत थी। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर 3.74 प्रतिशत रही है। वहीं, शहरी क्षेत्र में यह 3.16 प्रतिशत थी। अप्रैल में खाद्य मंहगाई दर 4.20 प्रतिशत रही है।

वैश्विक संकट के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाई मजबूती: गोयल

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और दुनिया का भरोसा भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट 2026' को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत हर वैश्विक संकट से पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए सरकार, उद्योग और आम नागरिकों के बीच बेहतर सहयोग बेहद जरूरी होगा।

गोयल ने भारतीय कंपनियों से घरेलू सप्लायर्स को प्राथमिकता देने और देश के भीतर औद्योगिक सहयोग मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक माहौल में 'सामान्य व्यापार' करने की सोच बदलनी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक अनुशासन और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हालिया अपील का जिक्र करते हुए कहा, आज हमें एक जागृति की जरूरत है। गोयल ने कहा,यह सरकार बनाम उद्योग का मामला नहीं है। यह सरकार, व्यापार, उद्योग और भारत के लोगों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में 'इंडिया स्पिरिट' का उल्लेख करते हुए कहा कि बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक दबावों के बावजूद भारत में हर चुनौती का सामना करने और खुद को मजबूत बनाने की क्षमता है।

उन्होंने कॉरपोरेट जगत को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारतीय कंपनियों को विदेशी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय घरेलू उत्पादकों और सप्लायर्स को समर्थन देना चाहिए। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के औद्योगिक समन्वय मॉडल का उदाहरण देते हुए गोयल ने कहा कि भारतीय उद्योगों को भी देश के भीतर मजबूत साझेदारी और सहयोग विकसित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, भारतीय उद्योगों को एक-दूसरे का समर्थन करना सीखना होगा। कोरिया और जापान के काम करने के तरीके को देखिए। गोयल ने आगे कहा, ₹हम कब तक इतने सीमित नजरिए से सोचते रहेंगे कि हमें यह समझ ही न आए कि भारतीय उद्योगों का सामूहिक हित हमारे व्यक्तिगत भविष्य को भी मजबूत करेगा। उन्होंने इसे केवल सुझाव नहीं बल्कि 'अनिवार्यता' बताते हुए कहा कि उद्योगों को भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

गोयल ने कहा, भारतीय स्टील को कोरिया और जापान जाने से रोकने के लिए सरकार की जरूरत नहीं है। उद्योग खुद सुनिश्चित करें कि वे एक-दूसरे का समर्थन करें। मंत्री की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब दुनिया भर के देश लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच सप्लाई चेन की मजबूती, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक व्यापारिक निर्भरता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

शेयर बाजारों में गिरावट जारी, प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत के करीब लुढ़के

मुंबई,एजेंसी। अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के पटरी से उतरने और रुपये पर जारी दबाव के कारण घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गयी और प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत के करीब लुढ़क गये। बीएसई का सेंसेक्स 1,456.04 अंक (1.92 प्रतिशत) टूटकर 74,559.24 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 436.30 अंक यानी 1.83 प्रतिशत नीचे 23,379.55 अंक पर बंद हुआ।

यह दोनों प्रमुख सूचकांकों का पांच सप्ताह का निचला स्तर है। शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन गिरावट रही है। खासकर, इस सप्ताह के पहले दोनों दिन बाजार में बड़ी बिकवाली देखी गयी है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इससे विदेशों में भी ज्यादातर प्रमुख शेयर बाजार फिसल गये।

इसके अलावा, रुपये के आज ऐतिहासिक निचले स्तर तक उतरने से भी बाजार में निवेश धारणा कमजोर हुई है। पहली बार एक डॉलर 95.50 रुपये प्रति डॉलर से ज्यादा का बोला गया है। फिलहाल यह 95.63 रुपये प्रति डॉलर पर है। चौतरफा बिकवाली के बीच मझोली और छोटी कंपनियों पर ज्यादा दबाव रहा। वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.43 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 3.17 प्रतिशत गिर गया।

सभी सेक्टर दबाव में रहे। रियलटी समूह का सूचकांक चार प्रतिशत से अधिक टूट गया। आईटी का सूचकांक पौने चार प्रतिशत और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद का साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा लुढ़का। ऑटो, मीडिया, रसायन, वित्त, बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा और स्वास्थ्य समूहों के सूचकांकों में भी एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट्स के शेयर साढ़े चार प्रतिशत के करीब लुढ़क गये।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज में चार प्रतिशत से अधिक और टीसीएस में पौने चार प्रतिशत की गिरावट रही। टाइटन, बीईएल, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर तीन प्रतिशत से ज्यादा गिरे। अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, इंडिगो और एलएंडटी के शेयर भी दो प्रतिशत दो से तीन प्रतिशत तक फिसल गये। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनीलिवर, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, सन फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत तक फिसल गये। एक्सिस बैंक का शेयर भी लाल निशान में रहा।

केंद्र ने ऑफशोर और डीपवाटर तेल एवं गैस ब्लॉक पर घटाई रॉयल्टी

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने डीपवाटर और अल्ट्रा-डीपवाटर ऑफशोर ब्लॉक से कच्चे तेल और केसिंग हेड कंडेनसेट उत्पादन पर रॉयल्टी को कम कर दिया है। यह जानकारी सरकार की ओर से ऑयल एंड गैस क्षेत्र में रॉयल्टी को लेकर जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में दी गई। नए संशोधित ढांचे के अंतर्गत, डीपवाटर क्षेत्रों के लिए रॉयल्टी कॉमर्शियल उत्पादन शुरू होने के पहले सात वर्षों के लिए 5 प्रतिशत और आठवें वर्ष से अधिक के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

अल्ट्रा-डीपवाटर क्षेत्रों से कॉमर्शियल उत्पादन पर पहले सात वर्षों तक कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। हालांकि, आठ वर्ष के बाद उत्पादन जारी रखने पर 5 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी। इसके अलावा, संशोधित रॉयल्टी अनुसूची में विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत आवंटित क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन-आधारित आवंटन, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) से पहले आवंटित ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)और डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड (डीएसएफ) नीति के तहत आवंटित क्षेत्र शामिल हैं।

स्थलीय और उथले जल क्षेत्रों के लिए, अधिकांश श्रेणियों में रॉयल्टी दर 12.5 प्रतिशत पर बनी हुई है, जबकि कुछ ऑफशोर और अल्ट्रा-डीपवाटर उत्पादन श्रेणियों पर कम रॉयल्टी लागू होगी। सरकार ने संशोधित ढांचे के तहत निर्दिष्ट कुछ श्रेणियों के लिए 7.5 प्रतिशत की रॉयल्टी दर को भी बरकरार रखा है। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं दबाव का सामना कर रही हैं।

इसके अलावा, सरकार ने कहा है कि हमारे पास पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा प्रस्तावित ईरान की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया और तेहरान के रुख को ₹पूरी तरह अस्वीकार्य₹ बताया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक प्रभाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करने के लिए नागरिकों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा कम करने और ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी।

वैश्विक तेल संकट के बीच भारत के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल ने मचाई धूम

नई दिल्ली, एजेंसी। मिडिल ईस्ट संकट के चलते वैश्विक सप्लाई में आई रुकावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल तेजी से भविष्य के टिकाऊ ईंधन के रूप में उभर रहा है। 'द टाइम्स कुवैत' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे सफल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बायोफ्यूल कहानियों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की लंबी अवधि की एथेनॉल ब्लेंडिंग रणनीति का बड़ा फायदा मिला है।

इससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत को होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से पैदा हुए तेल सप्लाई संकट के असर को कम करने में मदद मिली है, जिसने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है।रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने 2003 में केवल 5 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य से शुरुआत की थी। इसके बाद देश ने बायोफ्यूल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और अब पेट्रोल में लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है, वह भी तय समय से पहले। अब भारत ई85 पेट्रोल यानी 85 प्रतिशत एथेनॉल वाले ईंधन और मल्टीपल एथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए ई100 ईंधन की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 तक भारत में औसत एथेनॉल ब्लेंडिंग स्तर केवल 1.53 प्रतिशत था। हालांकि, लगातार सरकारी समर्थन, डिस्टिलरी क्षमता में निवेश और लंबी अवधि की योजना ने आज के तेज विस्तार की मजबूत नींव तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस अभियान का सबसे बड़ा मोड़ 2018 में आया, जब राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति लागू की गई। इससे कार्यक्रम का दायरा काफी बढ़ गया।

इसके तहत एथेनॉल उत्पादन को केवल गन्ने के शीरे तक सीमित न रखकर खराब खाद्यान्न, अतिरिक्त चावल, मक्का और कृषि अवशेषों तक बढ़ाया गया। इससे पानी की अधिक खपत करने वाले गन्ने पर निर्भरता कम हुई और उत्तर एवं मध्य भारत के अनाज उत्पादक क्षेत्रों को भी एथेनॉल अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जो पहल शुरुआत में केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पर्यावरणीय अभियान के रूप में शुरू हुई थी, वह अब ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और ग्रामीण विकास की व्यापक राष्ट्रीय रणनीति बन चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम भारत को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करके विदेशी मुद्रा में अरबों डॉलर की बचत करने में मदद कर रहा है। खासकर ऐसे समय में, जब पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एथेनॉल अभियान से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। बायोफ्यूल के लिए कच्चे माल की बढ़ती मांग से गन्ना किसानों, अनाज उत्पादकों, डिस्टिलरी उद्योग और बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लाभ हो रहा है। साथ ही कृषि, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'सिस्टम' का ट्रेलर रिलीज

दमदार लुक में अभिनेत्री आईं नजर

मुंबई। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की बहुप्रतीक्षित कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म सिस्टम का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया। अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सोनाक्षी एक सरकारी वकील नेहा राजवंश की भूमिका में हैं, जो ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर के साथ सत्ता और न्याय के बीच छिपी सच्चाई को उजागर करती हैं।

1 मिनट 59 सेकंड के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी शुरुआत एक जुनूनी युवा वकील नेहा (सोनाक्षी सिन्हा) से होती है। वह अपने पिता (आशुतोष गोवारिकर) की तरफ से मिली एक मुश्किल चुनौती को स्वीकार करती है ताकि वह उनकी फर्म में पार्टनरशिप की हकदार बन सके, लेकिन इस चुनौती को पूरा करना इतना आसान भी नहीं होता है, जिसके लिए वह सारिका (ज्योतिका) को अपने साथ शामिल करती है। वह एक तेज-तर्रार कोर्टरूम स्टेनोग्राफर है, जिसके मन में कुछ इरादे छिपे हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कोर्टरूम की जोरदार लड़ाइयों, उलझे हुए रिश्तों और कुछ दमदार पलों की एक तेज-तर्रार झलक देखने को मिलती है, जहां पर अमीरी के शोर में गरीबी की आवाज खो जाती है।

फिल्म का निर्देशन और सह-लेखन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया। उनका मानना है कि 'सिस्टम' जैसी तमाम कहानियां हमारे आस-पास ही होती है, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं। उन्होंने कहा, ₹मेरा मानना है कि हमारे आस-पास अनगिनत कहानियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें स्क्रीन पर पूरी सच्चाई और क्रिएटिविटी के साथ उतारना मुश्किल काम है। मुझे खुद को चुनौती देना पसंद है, और शायद इसीलिए मैंने 'सिस्टम' बनाई है। मैं बहुत खुश हूं कि प्राइम वीडियो ने हमारे विजन पर भरोसा किया।

उन्होंने आगे फिल्म के कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा, 'सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका जैसी दो दमदार महिला किरदारों के साथ काम करना, जो इस कहानी की जान हैं, मुझे पूरा यकीन है कि यह ओरिजिनल फिल्म न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करेगी, बल्कि भारत और दुनिया भर के दर्शकों के बीच सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत भी करेगी।'

फिल्म में अभिनेत्री सोनाक्षी नेहा राजवंश नाम की हाई-प्रोफाइल और महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (वकील) की भूमिका में हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया, 'इस किरदार को निभाना मेरे लिए बेहद संतोषजनक अनुभव रहा है। मुझे हमेशा ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, जो एक अभिनेता के तौर पर मुझे चुनौती दे और प्राइम वीडियो ने मुझे 'दहाड़' से लेकर अब 'सिस्टम' तक अलग अलग तरह की कहानियों और विषयों को आजमाने का मौका दिया है।

खुद को कैसे फिट और फाइन रखते हैं अमिताभ बच्चन, प्रशंसकों को खुद बताया सीक्रेट

नई दिल्ली। विश्व योग दिवस के करीब आने के साथ ही भारत सरकार का आयुष मंत्रालय योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है। मंत्रालय नए योगासनों की विस्तृत जानकारी, उनके फायदे और सही करने की विधि साझा कर आम लोगों को योग के प्रति लगातार प्रेरित कर रहा है। इसी क्रम में मंत्रालय ने अभिनेता अमिताभ बच्चन का एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

पोस्ट किए पुराने वीडियो में अमिताभ बच्चन आमजन को अपने स्वास्थ्य का राज बताते हुए रोजाना योग करने की सलाह दे रहे हैं। मंत्रालय ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "अमिताभ बच्चन से मिली प्रेरणा, जो आज आपको मैट पर ले आएगी यानी आप योगासन के प्रति उत्सुक होंगे। जब इस दिग्गज हस्ती ने खुद एक समृद्ध जीवन का अपना राज साझा किया था।"

वहीं, वीडियो में अमिताभ बच्चन स्पष्ट शब्दों में कहते नजर आते हैं, "मैं हर रोज योग करता हूं। इसने मेरे जीवन को संवारा और समृद्ध किया है। योग को अपनाकर जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जिया जा सकता है। ध्यान रखें कि योग हमेशा उचित मार्गदर्शन और परामर्श के साथ ही करना चाहिए।"

आयुष मंत्रालय का यह कदम विश्व योग दिवस (21 जून) की तैयारियों को और मजबूत बनाता है। मंत्रालय पहले भी कई योग गुरुओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सेलिब्रिटीज के माध्यम से योग के महत्व पर जागरूकता फैला रहा है। जो न केवल युवा बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए फायदेमंद है।

वास्तव में योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए भी बेहद उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। आयुष मंत्रालय विभिन्न योगासनों की विधि, सावधानियां और लाभों पर लगातार जानकारी दे रहा है।

नर्स बनाना चाहती थीं सनी लियोनी

पुरानी पहचान से पीछा छुड़ाकर बनीं बॉलीवुड की बड़ी स्टार

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने फिल्मों, गानों और रियलिटी शोज के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। हालांकि, उनकी जिंदगी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। एक समय ऐसा भी था, जब लोग उन्हें सिर्फ उनकी पुरानी पहचान से देखते थे, लेकिन सनी ने मेहनत और धैर्य के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की की। चमक-दमक की दुनिया में आने से पहले सनी का सपना नर्स बनने का था। वह मेडिकल फील्ड में जाकर लोगों की मदद करना चाहती थीं, लेकिन किस्मत उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले गई।

सनी लियोनी का असली नाम करनजीत कौर वोहरा है। उनका जन्म 13 मई 1981 को कनाडा के ओंटारियो में एक सिख पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन में सनी काफी शरारती स्वभाव की थीं। उन्हें खेलकूद में काफी रुचि थी। परिवार ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत कम उम्र से ही सनी लोगों की सेवा करना चाहती थीं। इसी वजह से उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई में रुचि दिखाई और मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देखा। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती थीं।

हालांकि जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सनी ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक जर्मन बेकरी में वेट्रेस की नौकरी की। इसके अलावा, टैक्स और रिटायरमेंट फर्म में भी काम किया। इसी दौरान उनकी जिंदगी धीरे-धीरे ग्लैमर इंडस्ट्री की ओर बढ़ने लगी। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्हें नई पहचान मिलने लगी।

बाद में उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया। इस दौरान उन्हें आलोचनाओं और तानों का सामना भी करना पड़ा।पुरानी चीजें सब छोड़कर सनी नई पहचान बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने भारत का रूख किया और पहली बार रियलिटी शो 'बिग बॉस' में नजर आईं। इस शो ने उन्हें भारतीय दर्शकों के बीच नई पहचान दिलाई। शो के दौरान ही मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म 'जिस्म 2' का ऑफर दिया। यही फिल्म उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत बनी।

विदेश

इजरायली हमले में लेबनान के 6 लोगों की मौत और 7 घायल

बेरूत। लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर इजरायली हमले जारी हैं। एक कस्बे पर इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों में छह लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी एनएनए ने इसकी जानकारी दी।

पाकिस्तानः केपी में धमाका, 7 की मौत और 23 घायल

पेशावर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित लक्की मरवत की सराय नौरंग तहसील में मंगलवार को एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में दो पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस के हवाले से मीडिया ने ये जानकारी दी।

इजरायल ने ईरान संघर्ष के दौरान यूएई को आयरन डोम बैटरी भेजीः अमेरिकी राजदूत

तेल अवीव। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने माना कि इजरायल ने यूएई को अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए आयरन डोम" मिसाइल रक्षा प्रणाली की बैटरियां और कुछ कर्मी भेजे थे।

वॉल्ट्ज ने सोमवार को यह टिप्पणी की थी, जिसे इजरायली अखबार 'इजरायल हयोम' ने प्रमुखता से छापा। वॉल्टेज के हवाले से लिखा कि "हमने देखा कि यूएई ने इजरायल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयरन डोम का उपयोग किया।"वहीं, इस बात की पुष्टि इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने भी एक कार्यक्रम में की।

उन्होंने तेल अवीव सम्मेलन में कहा, "मैं संयुक्त अरब अमीरात की सराहना करना चाहूंगा, जो अब्राहम समझौते का पहला सदस्य है। इसके लाभ देखे। इजरायल ने उन्हें आयरन डोम बैटरियां और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मी भेजे।"इन बयानों से इजरायल और यूएई के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संकेत मिलते हैं।

हकबी ने यह भी कहा कि वह "बहुत आशावादी" हैं कि मध्य पूर्व के अलावा विभिन्न देश जल्द ही अब्राहम समझौते में शामिल होंगे। यह 2020 का वह कूटनीतिक समझौता है जिसमें बहरीन और यूएई ने इजरायल को औपचारिक मान्यता दी थी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया, जिसके मुताबिक अप्रैल में ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जिससे वहां बड़ी आग लगी और उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा।हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ, उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की घोषणा कर रहे थे।

ईरान ने उस समय कहा था, 'रिफाइनरी दुश्मन के हमले में क्षतिग्रस्त हुई है।' इसके बाद तेहरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे।यूएई ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश को किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। अमेरिका इस हमले से नाराज नहीं था, क्योंकि उस समय सीजफायर पूरी तरह लागू नहीं हुआ था।अमेरिका ने चुपचाप यूएई और दूसरे खाड़ी देशों की भागीदारी का स्वागत किया। युद्ध के दौरान ईरान ने यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। इन हमलों का असर यूएई की एयर ट्रैफिक, पर्यटन और प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ा। कई जगह कर्मचारियों की छुट्टियां और छंटनी भी हुई।इन घटनाओं के बाद यूएई अब ईरान को क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा मानने लगा है। यूएई ने युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य सहयोग बनाए रखा।

अगर दोबारा हमला हुआ तो 90 प्रतिशत यूरेनियम संवर्धन करेंगेः ईरान

तेहरान। पश्चिम एशिया संकट फिर गहराने लगा है। अमेरिका के प्रस्तावों का ईरान की ओर से दिया जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया तो तल्ख बयानों की झड़ी लग गई। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर दोबारा हमला किया गया तो वह यूरेनियम संवर्धन की दर 90 प्रतिशत कर देगा।

ईरानी संसद की कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने दावा किया कि इस विकल्प पर संसद में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने 90 प्रतिशत संवर्धन की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की।यूरेनियम को 90 प्रतिशत तक समृद्ध करना हथियार स्तर का संवर्धन माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के मुताबिक ईरान पहले ही 60 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो वेपन ग्रेड के काफी करीब माना जाता है।

आईएईए की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने हाल के वर्षों में 60 फीसदी शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन तेज किया है।इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान भी बढ़ते तनाव और टकराव की तस्दीक करता है। उन्होंने कहा है कि ईरान में बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन के दोबारा होने की पूरी आशंका है।

ट्रंप के पहले चरण के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे एच.आर. मैकमास्टर का अनुमान है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू होगा। सीएनएन के एक शो में उनसे ट्रंप के उस बयान को लेकर सवाल किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ सीजफायर 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है।' यानी ये अत्यंत कमजोर स्थिति में है।सुर्खियों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणी भी है।

पाकिस्तानः खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में दो पुलिसकर्मियों समेत सात की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इन दिनों पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर हमला करने के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। स्थानीय मीडिया ने लोकल पुलिस से मिली जानकारी के हवाले से बताया कि मंगलवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले की सेराई नौरंग तहसील में हुए एक धमाके में दो पुलिसकर्मियों समेत कम से कम सात लोग मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने लक्की मरवत जिले के पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया कि इस घटना में 23 और लोग घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि इलाके में विस्फोटक ले जा रहा रिक्शा खड़ा था या किसी सुसाइड बॉम्बर ने उसे उड़ा दिया।बम डिस्पोजल स्क्वॉड के एक्सपर्ट ब्लास्ट की वजह का पता लगाने में लगे हुए हैं, जबकि मृतकों के शव को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया है, जबकि कुछ घायलों को बन्नू के हॉस्पिटल में ले जाया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए वीडियो में ब्लास्ट में कई दुकानें और तीन पहिए वाली गाड़ी क्षतिग्रस्त दिखे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना की जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम ने इलाके को घेर लिया और सबूत इकट्ठा किए।यह घटना रविवार सुबह बन्नू में एक चेकपॉइंट पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 15 पुलिसवालों के मारे जाने के बाद हुई। इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान (आईएमपी) नाम के एक उग्रवादी समूह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उस बम धमाके की जिम्मेदारी ली।

ब्रिटेन : स्टार्मर की मंत्री ने दिया इस्तीफा, पीएम से देश हित में की खास अपील

लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मंत्री मियाटा फैनबुले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कैबिनेट की पहली मंत्री हैं जिन्होंने ये कदम उठाया। इतनी ही नहीं उन्होंने पीएम से भी अपना पद छोड़ने की अपील की है।

ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक मंत्री मियाटा फैनबुले (डिवॉल्यूशन, फेथ एंड कम्युनिटीज डिपार्टमेंट) ऐसी पहली मंत्री बन गई हैं जिन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से इस्तीफा मांगा है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मियाटा फैनबुले ने पीएम को लिखा अपना खत साझा किया। उन्होंने लिखा, 'मैं यह पत्र आपको डिवॉल्यूशन, फेथ एंड कम्युनिटीज़ मंत्री के पद से अपना इस्तीफा देने के लिए लिख रही हूं।'

इसके साथ ही, उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाईं।

उन्होंने लिखा कि मुझे इस सरकार में किए गए अपने कार्य पर गर्व है। पहले ऊर्जा उपभोक्ता मंत्री के रूप में, मैंने 60 लाख परिवारों के लिए ऊर्जा बिल में छूट सुनिश्चित की और हमारे "वॉर्म होम्स प्लान" को शुरू किया। अपने वर्तमान पद पर, मैंने "प्राइड इन प्लेस प्रोग्राम" लागू किया, इंग्लिश डिवॉल्यूशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट एक्ट के माध्यम से शक्ति के वितरण में बड़ा बदलाव लाया, और समुदायों में बढ़ती नफरत और विभाजन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण काम किया।

फैनबुले ने लेबर पार्टी की गिरती साख को इस्तीफे की वजह बताई। लिखा, 'हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन हमने अपने जनादेश के अनुसार दृष्टि, गति और महत्वाकांक्षा के साथ काम नहीं किया है। न ही हमने लेबर पार्टी के रूप में अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ स्पष्ट रूप से शासन किया है। सर्दियों के ईंधन भुगतान और दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली सहायता में कटौती जैसे फैसलों ने मेरे क्षेत्र के कई लोगों को हमारी नीयत पर संदेह करने के लिए मजबूर किया है। और जनता का संदेश स्पष्ट था—आप, प्रधानमंत्री, ने जनता का भरोसा और विश्वास खो दिया है।'स्टार्मर से पद छोड़ने की अपील करते हुए, उन्होंने आगे कहा, 'जनता को विश्वास नहीं है कि आप इस बदलाव का नेतृत्व कर सकते हैं, और मुझे भी नहीं है।